[Shri L. N. Mishra]

about the proposals both in respect of freight rates and passenger fares.

All these measures which will be effective from 1-4-1974 will bring in a total additional revenue of Rs. 136.38 crores during 1974-75. This will leave an uncovered gap of Rs. 52.79 crores in the payment of dividend to the General Revenues.

We are living through difficult times and the challenges arising out of the economic stresses, inflation, and oil crisis, etc., require the best effort from all of us. Indiscipline has no place in such a situation and must be replaced by hard work. Any institution is as good as its men, and this is particularly true in the case of Railways, which is the least officered amongst public and private undertakings. This caste a heavy responsibility on railway workers, particularly as in the context of high prices of oil our economy is going to be more dependent on rail transport than hitherto. I appeal to all sections of railwaymen to rise to the occasion, sink their differences and render a good account of themselves in service of the Nation. I sincerely hope that my appeal will not go in vain. I have done Thank you.

MR. SPEAKER : In order to keep strictly within the time, the Minister has skipped over some portions of his printed speech. These have been taken as read—The Minister should say that.

SHRI L. N. MISHRA : Yes, Sir.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : He did not take your permission. Why oblige him?

MR SPEAKER : He came to me earlier The Secretary-General brought it to my notice. I said it is all right

Now we adjourn for lunch to re-assemble at 2.30 P.M

13.20 hrs.

[The Lok Sabha adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.]

[The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-five Minutes past Fourteen of the Clock.]

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*].

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति महोदय के ऊपर संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करने का दायित्व डाला है । राष्ट्रपति जी निष्ठापूर्वक दायित्व का पालन करते है । बजट अधिवेशन के प्रारम्भ मे वे कई घोड़ो की बग्घी पर आते है, उन के सिर पर एक चमकता हुआ छत्र होता है, चोबदार हाज़री देते है, बिगुल बजते है और राष्ट्रपति महोदय लिखा-लिखाया भाषण पढ कर अपने निवास-स्थान को लौट जाते है ।

कुछ मित्रो ने इसे अनावश्यक कर्मकाण्ड कहा है । मुझे तो यह सारा दृश्य प्रहसन-सा प्रतीत होता है । राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नही, उस पर होनेवाली यह चर्चा, चर्चा करने वाला यह सदन, यह संसद कुछ अर्थों मे बेमानी, व्यर्थ, जन-जीवन से कटा हुआ, वास्तविकता से दूर का दृश्य दिखाई देता है ।

यह लोक सभा है, किन्तु यह लोक-शक्ति का प्रतिनिधित्व नही करती, यहा तक कि सही-सही रूप में उसे प्रतिबिम्बित भी नही करती । यह सदन राज-शक्ति का एक आकर्षक अलंकरण-मात्र बन कर रह गया है । प्रतिपक्ष इतना दुर्बल है कि शोर मचाने भर मे समर्थ है । सत्ता पक्ष इतना भारी-भरकम है कि अपने ही बोझ के नीचे दबा जा रहा है ।

1971 में सत्ता पक्ष को दो-तिहाई से अधिक बहुमत मिला, किन्तु उस बहुमत से देश को क्या मिला ? आम आदमी ने क्या पाया ?

राजाओं के जेब-खर्चे की समाप्ति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को प्रगति की परम-उपलब्धि मान कर चलनेवाला शासनारूढ दल तीन साल बाद ही बुन्देलखण्ड के चुनावों को जीतने के लिये पुराने राजाओं की शरण में चला गया । सुरक्षा मंत्री श्री जगजीवन

राम को मुरादाबाद में यह स्वीकार करना पड़ा कि बैंक-राष्ट्रीयकरण विफल हो गया है, क्योंकि उस से जिन को लाभ मिलना चाहिये था उन को लाभ नहीं मिला।

प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा के चुनावों को विधान सभा के चुनावों से अलग कर के चुनावों को न केवल अधिकाधिक खर्चीला बना दिया है बल्कि सत्ता पक्ष को चुनावों में ऐसा रवैया अपनाने के लिये विवश किया है जिसे न स्वस्थ कहा जा सकता है और न राष्ट्रीय एकता के लिये हितावह। उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रधान मंत्री जी द्वारा बारबार यह कहना कि यदि लोगों ने सत्ता पक्ष को वोट नहीं दिया तो उन के प्रदेश की प्रगति रुक जायेगी, राजनैतिक ब्लैक-मेल के अलावा कुछ नहीं है।

23 दिसम्बर, 1973 को धेनकनाल में भाषण करते हुए प्रधान मंत्री जी ने कहा--लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो उन्हें केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ेगा। इस आशय का एक तार श्री पटनायक ने चुनाव आयोग को भेजा है। बाद में वह पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। प्रधान मंत्री जी की ओर से उस का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार की धमकियां चुनाव को न केवल मखौल बना देती हैं, केन्द्र के विरुद्ध भी भावनायें भड़काती हैं। इस से राष्ट्र की एकता पर कुठाराघात हो सकता है। हम सबल केन्द्र चाहते हैं, लेकिन केन्द्र की सबलता संविधान से आती है, किसी दल के सत्ता पर एकाधिकार से नहीं आती। यदि केन्द्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया तो प्रदेशों में केन्द्र विरोधी भावनायें उभर सकती हैं और यह देश के लिये एक दुर्भाग्य की बात होगी।

इस सरकार ने दिल्ली कारपोरेशन के हाथ से गन्दी बस्तियों की सफाई का काम छीन लिया है। ऐसा क्यों किया गया है, मैं यह समझने में असमर्थ हूं। इस से पहले डी० टी० यू० कारपोरेशन से हटा कर एक स्वायत निगम को दे दी गई। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली कारपोरेशन में जनसंघ का बहुमत है और सत्तारूढ़ दल उस बहुमत को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

चुनाव के पूर्व उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाओं के शिलान्यासों की जो बाढ़ आई उस ने केन्द्रीय सरकार के पक्षपाती स्वरूप को बेनकाब कर दिया है। 550 करोड़ की योजनाएं--चुनाव के समय उन योजनाओं का शुभारंभ या उद्घाटन या शिलान्यास क्या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं था? क्या यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? हिन्दुस्तान टाइम्स का मैं एक सम्पादकीय उद्धृत करना चाहता हूं। किसी भी कल्पना से इसे कांग्रेस का विरोधी नहीं माना जा सकता/किन्तु पत्र निष्पक्ष और निर्भीक है :

"The series of two special reports entitled 'Foundations of Electoral Success', concluded elsewhere on this page, presents a catalogue that does the Prime Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh little credit in larger terms of liberal principles, democratic values, economic discipline or national example. Perhaps some of the electorate, too might be more annoyed than flattered by all these blandishments. Not everything that has been done is by any means wrong. But, as the Supreme Court has ruled, "energy to do public good should be used not on the eve of elections but much earlier' —and, we would urge, elsewhere too. The Central leadership, governmental or party, has had little time for Gujarat or the deepening economic crisis. There is a large grey area in politics. But the grey should not assume a darker shade. Even if the Congress is conceivably not guilty of electoral mal-practice in U.P., not a few of its actions come dan-

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

gerously close to unfair practice. And Mrs. Gandhi, alas, stands greatly diminished.

Uttar Pradesh goes to the polls within a fortnihgt. The Congress may win the election, it may not. Whatever the result, this much is certain, India has lost."

550 करोड़ की योजनाए चुनाव के अवसर पर प्रारंभ करने वाला दल इस बात का सबूत देता है कि वह 4 साल 10 महीने सोता रहा और चुनाव की पराजय सम्मुख देख कर अचानक सक्रिय बन गया ।

29 दिसम्बर, 1973 को सूपूं, कनारा, में भाषण करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था—

"The worst was over in the country's economy and from the next month onwards, the things will improve for the better. Food shortage will be a thing of the past."

यह प्रधान मंत्री का 29 दिसम्बर का भाषण है । उन के आर्थिक सलाहकार कौन है यह मै समझने में असमर्थ हूं । कौन उन्हें तथ्यों से अवगत कराता है यह भी एक रहस्य का विषय है । स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी है । संकट गंभीर रूप ले रहा है । अन्न का अभाव विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है । फसल अच्छी हुई है किन्तु गलत नीतियों ने कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया है ।

हमारी अर्थव्यवस्था त्रिदोषों से ग्रस्त है । ये, त्रिदोष हैं—(1) मुद्रा-स्फीति, (2) काला धन और तीसरा भ्रष्टाचार । रुपये के मूल्य मे निरंतर गिरावट पैदा हो रही है । इस से एक भयावह परिस्थिति का निर्माण हो रहा है । वित्त मत्री ने 27 नवम्बर, 1973 के उत्तर में बताया है कि 1947 के उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक को आधार मान कर लगाए गए हिसाब के अनुसार रुपये की क्रय शक्ति 1950 में 99 पैसे, 1960 में 80 पैसे, 1970 में 44 पैसे और 1973 में 36 पैसे रह गई है । अभी भी बाजार में रुपये के बदले 100 पैसे मिलते हैं । लेकिन सौ पैसे की कीमत 36 पैसे है । हमारे विद्यार्थियो को अब नया गणित सीखना पड़ेगा कि एक रुपया बराबर 100 पैसे और 100 पैसे बराबर हैं 36 पैसे । यदि इस गति से रुपये की कीमत गिरती है और मुद्रा-स्फीती बढ़ती है तो आम आदमी का जीवन अधिक दुखी होने से नहीं बचाया जा सकता । अन्धाधुन्ध नोटों की भरमार मुद्रास्फीती का मुख्य कारण है । 1965-66 मे जनता के पास 4529 करोड़ के नोट थे और 1971 मे वह 10,061 करोड़ के हो गए इस की तुलना में विकास की दर निरंतर गिरी है । 1969-70 मे विकास की दर 5.3 प्रतिशत थी, 70-71 में 4.2 प्रतिशत, 71-72 में 1.7 प्रतिशत और 72-73 मे 0.6 प्रतिशत विकास की दर है ।

काला धन हमारी अर्थ-व्यवस्था को खोखला कर रहा है । काले धन की एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था देश मे चल रही है । जो चुनाव लड़े जाते है वह काले धन से लड़े जाते हैं । कोई भी दल उस से मुक्त नही है । इस संसद का, लोक तंत्र का सारा भवन झूठ पर खड़ा है । पार्लियामेंट का मेम्बर, असैम्बली का मेम्बर पहला जो काम करता है वह झूठा हिसाब दाखिल करता है । सत्यमेव जयते का नारा लगा कर हम यहा एकत्र हुए हैं मगर हम सब के मूल मे असत्य छिपा हुआ है । क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रधान मंत्री ने 12 हजार रुपए का अपने चुनाव क्षेत्र का व्यय का हिसाब दिया है । 12 हजार रुपये मे कोई चुनाव लड सकता है ? मगर हिसाब दिया गया है ।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): On a point of order. Mr. Vajpayee has said, 'the entire House'. He has not made any exception. He can speak for himself; he can speak for those about whom he knows....

MR. DEPUTY-SPEAKER : It has gone on record. No point of order.

SHRI S. A. SHAMIM : Will you allow me to clarify, Sir? He has said, 'the entire House'. He must make one honourable exception, and that is myself.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : I do.

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार एक भयंकर रूप धारण कर रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा जब प्रधान मंत्री ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल में एक ऐसे सज्जन को शामिल किया है जिन्हें दस साल पहले श्री जवाहर लाल नेहरू ने

'high principles of Parliamentary democracy by which the office of a Minister is governed'.

के आधार पर..........

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Put the facts straight. He resigned.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब उन्होंने रिजाइन किया तब उन्होने भी यह कहा कि मैं कुछ मूल्यों मे विश्वास करता हूं और उन मूल्यों की रक्षा के लिए त्यागपत्र दे रहा हूं। क्या आज उन मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है? क्या आज उन मूल्यों की कीमत नहीं रही? क्या मंत्री के आचरण के मापदण्ड बदल गए?

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज): क्या कोई आदमी पीछे चल कर अच्छा नहीं हो सकता है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, अगर आप का यह कहना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रधान मंत्री को शिकायत है कि विरोधी दल आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार की गलत और अदूरदर्शी नीतियों से उत्पन्न जन-असंतोष को मुखरित और संघटित करना हमारा धर्म है और हम उस धर्म का पालन करेंगे। किन्तु जिन्होंने 1972 की राष्ट्रीय विजय को दलगत सफलता के लिए प्रयुक्त करने में संकोच नहीं किया उन के मूंह से ऐसा आरोप शोभा नहीं देता। जो कांच के घर में बैठ हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने की भूल नहीं करनी चाहिए।

प्रधान मंत्री को ताज्जुब है कि जो सबसे अधिक गरीब हैं वे तो चुप हैं, किन्तु जिन की हालत बेहतर है वह आन्दोलन कर रहे हैं। मैं उन के शब्दों का उद्धत कर रहा हूं —

"The very poorest were not complaining or non-cooperating or having strikes, but the people who were comparatively better-off."

क्या इस को समझने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता है? जो बिलकुल गरीब है वे मूक हैं, बिखरे हुए हैं, शताब्दियों से कुचले हुए हैं, वे नहीं लड़ सकते। वे सड़क पर ठिठुर कर मर सकते हैं, कपड़े की दूकान नहीं लूट सकते। वे भूख से जान दे सकते हैं पर अन्न के गोदाम नहीं लूट सकते। इस के विपरीत जिन की दशा अपेक्षाकृत अच्छी है, जो जागृत हैं, संगठित हैं, वे परिवर्तन के नये रास्ते अपनाएंगे। जो बिल्कुल गरीब हैं वह भाग्य के भरोसे बैठा है। मगर जिस में थोड़ी सी भी जागृति आयी है वह अपने भाग्य को बदलने के लिये संघर्ष कर रहा है। यही कारण है आज छात्र, अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर जूझ रहे है। दमन चक्र के बजाय सरकार को उन की मनोवस्था को समझने का यत्न करना चाहिए।

दिल्ली के जूनियर डाक्टर क्या मांग रहे हैं? कल डा० कर्ण सिंह ने अपने लम्बे भाषण में अध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की। जो डाक्टर उन के घर के बाहर बैठे हैं उन की मानवता का भी उन्होंने एक दृश्य उपस्थित किया? मगर यह सरकार स्वयं हृदयहीन हो गई है। वह जूनियर डाक्टरों से ठीक से बात तक नहीं करती। वह किस तरह से काम के घंटों में लगन से परिश्रम से मरीजों की देखभाल करते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वे 500 रु० वेतन मांग रहे हैं, सिटी अल.उन्स मांग रहे हैं, नान-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स मांग रहे हैं क्या उन्हें 650 रु० देना उन के ऊपर बड़ा भारी एहसान हो गया है? सरकार क्या देना

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

चाहती है, यहाँ तक बताने के लिये तैयार नहीं है। वह हड़ताल को तोड़ने पर आमादा है। इस में से बगावत के बीज निकलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप को सुन कर ताज्जुब होगा, मुझे अफसोस है प्रधान मंत्री जी सदन में नही हैं, बाद में आ कर कहेगी कि मैं कमरे मे बैठ कर भाषण सुन रही थी, रायबरेली मे वहां के विद्यार्थियों को इसलिये पुलिस ने गिरफ्तार किया क्यो कि राययबरेली के फ़ीरोज़ गांधी मेमोरियल कालेज के छात्र यूनियन का उद्घाटन करने के लिए उन्होने मुझको बुलाने की गलती की। विद्यार्थी पकड़े गये, रात मे पकड़े गये, हथकड़ी लगा कर उन्हें कोतवाली ले जाया गया, पीटा गया। कभी आप ने सुना है कि विद्यार्थियों पर यह शर्त लगायी जाय कि हर तीसरे दिन कोतवाली मे आ कर हाजिरी दे ? विद्यार्थी न हो गये, अपराधी हो गये वे माग क्या कर रहे है ? यही कि कालेज मे प्रोफैसर समय पर नियुक्त होना चाहिये, लायब्रेरी से 15,000 रु० की किताबे गायब है उन का हिसाब मिलना चाहिये। लायब्रेरी फ़ीस 15 रु० ली जाती है जिस में से 3 रु० की रसीद तक नही दी जाती है। वह कहते है कि रसीद दी जानी चाहिये। मेडिकल के लिये मैगजीन के लिये जो रुपया इकट्ठा किया जाता है उस का सदुपयोग होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियर भी कोई चाद का टुकडा नही माग रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन माग रहे हैं। 50 परसेंट पदोन्नति माग रहे है। मगर उन्हें भी दबाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, दमन ग्रान्दोलन में आग का काम करते है। गोलिया चला कर लोगो को मारा जा सकता है मगर गोलिया चला कर लोगो के दिलो पर राज्य नही किया जा सकता। गुजरात एक चेतावनी है, गुजरात एक चुनौती है। चेतावनी उन भ्रष्ट सत्ता लोलुपों के लिये जो अनैतिक तरीके अपना कर हुकूमत हथिया लेते है, मगर जो जनता की अपेक्षाओं और शासन की उपलब्धियों में बढ़ती हुई खाई को नजर-अंदाज करना चाहते हैं। गुजरात चुनौती है उन सब के लिये जो शांतिपूर्ण मार्ग से इस देश में परिवर्तन करना चाहते हैं।

गुजरात के जन विद्रोह को पूजीपतियो द्वारा प्रेरित बता कर प्रधान मंत्री ने न केवल इतिहास को बदलने वाली नई शक्तियो को समझने में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है अपितु गुजरात की जनता का अपमान भी किया है। भाडे के लोग प्रधानमंत्री की जयजयकार के लिये भले ही जमा किये जा सकें, उन्हें कोई पुलिस की गोली खाने के लिये तैयार नही कर सकता। गाधीवादी विचारक, प्रो० अमृतानन्द के शब्दो में —

"We can describe the Gujarat popular upsurge as a movement of self-disciplined protest and violence, directed against a corrupt and inefficient system and based on popular and decentralised leadership."

उपाध्यक्ष महोदय, बगला देश की विजय का लाभ उठा कर और राजनीतिक स्थिरता का नारा देकर, विधान सभाओ के चुनाव जीत लिये गये। किन्तु प्रधान मंत्री राज्यो में एक ईमानदार और सक्षम प्रणाली, जिसका आधार सस्ता लोक-प्रियतावाद नही, चीप पौपुलिज्म नही. रेडिकल रियलिज्म, क्रान्तिकारी यथार्थ-वाद हो, ऐसी प्रणाली नही दे सकीं। परिणाम सामने है। गुजरात जल रहा है, महाराष्ट्र में चिनगारिया सुलग रही है और सारा भारत क्रान्ति के कगार पर खड़ा है।

प्रधान मंत्री गुजरात की विधान सभा को भंग करने के लिये तैयार नही है। किन्तु जब केरल में ऐसा ही मास अफसर्ज हुआ था और प्रथम कम्युनिस्ट सरकार अप-

दस्त कर दी गई थी तब विधान सभा भंग की गई थी या नहीं की गई थी ? तब प्रधान मंत्री कांग्रेस की अध्यक्षा थीं। मगर जो विधान सभा भंग की गई थी उसमें कम्युनिस्टों का बहुमत था इसलिये उस को भंग कर दिया गया। गुजरात की विधान सभा को इसलिये भंग नहीं किया जा रहा है .....

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Not a single MLA was assaulted in Kerala like this. You are defending fascism now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि कांग्रेस बहुमत में है। यह दोहरा मापदंड, यह दुरंगी राजनीति, यह नग्न सत्तावाद ही आज का सब से बड़ा अभिशाप है। इसी के चलते मुस्लिम लीग केरल में असाम्प्रदायिक हो जाती है और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक बन जाती है। शिवसेना का बम्बई में समर्थन किया जाता है और शेष भारत में उसके विरोध का ढोंग रचा जाता है। पांडिचेरी मे संगठन कांग्रेस को गले लगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में दुरदुराया जाता है। कम्युनिस्टों के साथ प्यार और तकरार का नाटक एक साथ चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री दिल्ली में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भाषण देती है, किन्तु उत्तर प्रदेश में खुले आम उन्होने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को भड़काया। हरदोई में 14 फरवरी को भाषण देते हुए उन्होंने ने कहा, मैं "नेशनल हैराल्ड" से उद्धृत कर रहा हूं :

> The PM said that the Muslims should not divide themselves as in that case they would grow weaker and would not be able to guide their own destiny.

क्या मतलब है इस का ? क्या यह राष्ट्रीय एकता की अपील है ?

श्री एस० ए० शमीम : वह आप से बचने के लिए कहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुसलमानों को यह कहना कि अपनी इच्छानुसार वोट न दें, पार्टियों के प्रोग्राम के अनुसार वोट न दें, मुसलमान के नाते वोट दें, एक साथ वोट दें, यह अलगाव को बढ़ाने वाली बात नहीं है ?

इतना ही नहीं उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली में मुस्लिम लीग की जो शाखा खुली है उस के संयोजक एक मुस्लिम नौजवान को जनसंघ ने पैसा दिया है। प्रधान मंत्री को मालूम होना चाहिये कि दिल्ली में मुस्लिम लीग हाल में नहीं बनी, 1968 में बनी थी। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके कर्त्ताधर्त्ता मिर्जा मुहम्मद उस्मान थे जो प्रधान मंत्री की पार्टी के टिकट पर कोरपोरेशन के मेम्बर चुने गये थे, बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गये। प्रधान मंत्री जनसंघ के विरुद्ध अपना आरोप साबित करें या उन्हें उस आरोप को वापस ले लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मै समाप्त करना चाहता हूं। आकर्षक नारे लगा कर, पानी की तरह से पैसा बहा कर शासन तन्त्र का खुला दुरुपयोग कर के सत्ता पर कब्जा करना असम्भव नही है। लेकिन सत्ता किसलिये ? क्या सत्ता सत्ता के लिये, या सत्ता समाज परिवर्तन के लिये ? क्या सत्ता केवल उपभोग के लिये ? क्या सत्ता कालपात्र में दबाये गये इतिहास में अपना नाम लिखाने भर के लिये या सत्ता दूसरों के नाम कटवाने भर के लिये ? क्या सत्ता मात्र अहम की संतुष्टि के लिये ? सत्ता का प्रयोजन क्या केवल यही है ? क्या सत्ता किसी बन्दरगाह, किसी नहर, किसी विश्वविद्यालय का नाम अपने नाम पर रखने के लिये ?

आजादी के 25 साल बाद भी भारतीय समाज जड़ता में, अंधविश्वास में, कुरीतियों

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

में, छूआछूत में डूबा हुआ है। हमने समाज को बदलने के लिये क्या किया है? भारत की प्रधान मंत्री एक महिला हैं। किन्तु करोड़ों महिलाएं नारकीय जीवन बिता रही हैं, उन के मुख पर घूंघट पड़े हैं, बुरखे लटके हैं। शारदा कानून ने बाल विवाह बन्द कर दिये। किन्तु प्रतिवर्ष लाखों बच्चों के पालने में विवाह होते हैं। दहेज के विरुद्ध कानून बना है। किन्तु दहेज बढ़ गया है। दहेज के प्रभाव में जवान लड़कियो जान तक दे बैठती हैं। अच्छे अच्छे घरो में पर्याप्त दहेज न होने के कारण बहुओं के साथ आज भी दुर्व्यवहार होता है।

अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है किन्तु हरिजन जिन्दा जलाये जाते हैं। उनकी महिलाओं का शरीर सार्वजनिक रूप से गरम चिमटे से दागा जाता है। क्या प्रधान मन्त्री इन कुरीतियों के विरुद्ध जेहाद नही छेड़ सकतीं? क्या वे हिन्दुओं, मुसलमानो मे नहीं कह सकतीं कि उन्हें वक्त के साथ बदलना होगा? क्या वे मुस्लिम पर्सनल ला में संशोधन की बात पर दृढ़ता से नही अड़ सकतीं? मगर उन्हें वोट चाहिये।

श्री एम० ए० शमीम : आपको क्या दर्द है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय पहले इनको बदलना जरूरी है।

जितना समय जितनी शक्ति, जितने साधन प्रधान मंत्री ने एक प्रदेश मे अपनी पार्टी को चुनाव जिताने पर लगाया उतना यदि वह सामाजिक, क्रांति का सूत्रपात करने में लगाती तो देश का नक्शा बदला हुआ नजर आता। लेकिन अफसोस है कि प्रधान मंत्री ने मिले हुए समय को खो दिया। आज खतरे की घंटी बज रही है, हम सब के लिये बज रही है। एक व्यवस्था टूट रही है। एक प्रणाली अस्त-व्यस्त हो रही है। यह केवल एक दल का प्रश्न नहीं है, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज दांव पर लगी हुई है।

15.00

पुराने मूल्य ठुकरा दिए गए हैं, किन्तु नए मूल्य अभी तक स्थापित नहीं हुए है, पुराने श्रद्धा केन्द्र ढह चुके हैं, नए श्रद्धा केन्द्र हम खड़े नहीं कर सके हैं, पुराना युग मर रहा है लेकिन नया युग जन्म नही ले रहा है। देश आज चौराहे पर खड़ा है। यह निर्णय की घड़ी है। चुनाव, वोट, सत्ता की राजनीतिक, इनकी सीमाए हैं। लेकिन उन सीमाओं को तोड़ कर अगर हम नहीं निकल सकते हैं तो एक महान भारत की रचना का स्वप्न कभी साकार नही कर सकते।

प्रधान मंत्री ने जन-अपेक्षाओं का जो ज्वार जगाया है वह आज उनके सिंहासन को हिला रहा है। यदि समय रहते वह नही सहम्लती तो उनकी भी वही गति होगी तो चिमन भाई पटेल की गुजरात में हुई।

श्री शशि भूषण (दक्षिणी दिल्ली) : मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने देश की स्थिति से लोगों को अवगत कराया है और साथ साथ उन्होने नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये हमारा आह्वान किया है।

अभी-अभी हमने वाजपेयी जी का भाषण सुना। एक तरफ उन्होंने सामाजिक क्रान्ति की बात कही। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जब भी समाज में नए कदम हमने उठाए, उन पर उन्होंने कुठाराघात किया। बिरादरीवाद, जातिवाद, पुराने आडम्बर, पुरानी संस्कृति का झंडा लेकर आज सामाजिक क्रान्ति की बात वह करते हैं। अच्छा होता कि वाजपेयी जी वास्तव मे इस देश में जो सामाजिक क्रान्ति की जा रही है उसको समझते और यह भी समझते

कि आज हम लोग महात्मा कबीर युग से भी पीछे चले गए हैं, स्वामी दयानन्द के समय से भी पीछे चले गए हैं। इस प्रजातंत्रीय आड़ में बिरादरीवाद, जातिवाद और ढोंग जो भरा पड़ा है, उसके खिलाफ हम सब को कटिबद्ध होकर लड़ना होगा। देश से गरीबी दूर करने का हम लोगों ने प्रण किया है। लेकिन गरीबी दूर करने के लिए पहले अमीरी को जरूर दूर करना होगा। अमीरी को जब दूर करने की कोशिश की जाती है तो जो लोग आज सामाजिक क्रान्ति की बात करते हैं वे आर्थिक क्रान्ति से बचने के लिए राजा महाराजाओं और आढ़तियों की रक्षा करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि जो झंडा अंग्रेजों के जमाने में यूनियन जैक के साथ साथ फहराता था और जिन झंडों को अंग्रेज बैन नहीं कर सके, किसी कीमत पर नहीं कर सके वही हरे और भगवे झंडे लाखों की तादाद में हमने चुनाव में बाजारों आदि में फह-राए जाते देखा, बाजार इनसे भरे पड़े देखे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके पास पैसा कहां से आता है। हम से कहा जाता है कि हम शासक दल के हैं, पैसा हमारे पास बहुत है लेकिन इनके पास कहां से हमसे ज्यादा पैसा आता है यह भी तो ये बताएं। जो झंडे काले इतिहास के प्रतीक हैं, जिन झंडों को लेकर प्रातः परेड करते हुए होम-गार्ड में लोगों को भरती कराया गया, अंग्रेजी फोज में हिन्दुओं और मुसलमानों को भरती कराया गया वही झंडे आज किसी के लिए बड़ी श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए वे काले इतिहास के प्रतीक हैं और उसी की हम को सदा याद दिलाते हैं। हमने इन झंडों का नजारा देख लिया है। जहां जहां इनको लगाया जाता है वहां वहां इनकी हार होती है और हुई है। भगवे और हरे झंडे लेकर उन्होंने जिस किसी की भी रक्षा करने की कोशिश की है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। राजा महाराजाओं की रक्षा करने की कोशिश की उनका बेड़ा गर्क हुआ, बैंक मालिकों की करने की कोशिश की, उनका बेड़ा गर्क हुआ और आज यह हिन्दुस्तान के उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन के पास दस हजार करोड़ रुपया ब्लैक का है और उनका भी भगवान ही मालिक है। भगवे झंडों को लेकर पीछे चुनाव में इन्होंने चार पार्टियों का एक गुट बनाया, उन चारों का बेड़ा गर्क हो गया। ये ऐसे झंडे हैं जोकि देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाए जाने के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं।

बंगला देश में ब्रह्मपुत्र की नदी में बच्चों, और बूढ़ों औरतों का खून बह रहा था तब यहां हिन्दुस्तान के नौजवानों का खन खौल रहा था। बंगला देश की सुरक्षा के लिए और खास तौर से वहां से जो शरणार्थी आए उन पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपया हम को व्यय करना पड़ा। आज भी हमारे सामने नए चैलेंज हैं। डिएगो गार्शिया में वही साम्राज्यवादी झंडा मौजूद है जो हिन्दुस्तान में कभी साम्राज्यवादियों का झंडा था, यूनियन जैक आज वहां मौजूद है। अमरीका का झंडा भी उसके साथ-साथ वहां फहरा रहा है, वह भी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। जिन साम्राज्यवादियों के खिलाफ हमने आजादी की जंग लड़ी थी उन साम्रा-ज्यवादियों के एजेंट आज भी देश में मौजूद हैं। चीन भी आज डिएगो गार्शिया में अमरीका और ब्रिटेन की सहायता कर रहा है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अमरीका एक नया बन्दर-गाह बनाने जा रहा है। कराची से 21 मील की दूरी पर चीन एक बन्दरगाह बना रहा है। आज पाकिस्तान के अन्दर भी कुछ विदेशी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को गुलाम बनाने में लगी हुई हैं। सिन्ध नदी में पख्तूनों, बलोचियों और सिन्धियों का

[श्री शशि भूषण]

खून बह रहा है । पाकिस्तान की आजादी को खतरा है । हम भी अपने चारों तरफ खतरा देख रहे है ।हमारी सीमाओं पर आज लाखों की तादाद में चीनी सैनिक मौजूद हैं । उसने कैंटन से अपना कैंटोनमेंट हटा कर हमारी सीमा की ओर निर्माण कर लिया है । चारों तरफ साम्राज्यवादी ताकतें हमें चुनौती दे रही हैं । हिन्दुस्तान बेरोजगारी के कारण परेशान है, आर्थिक कठिनाइयो में फंसा हुआ है । ऐसी अवस्था में जो लोग साम्राज्यवादियों का साथ देते हैं वे हिन्दुस्तान की आजादी और हिन्दुस्तान के स्वाभिमान के साथ क्या खिलवाड़ नही करते है और क्या यह देशद्रोही नहीं है । देश में साम्राज्यवादियों के खिलाफ जो एक आजादी की जंग पहले लड़ी गई उस वक्त भी वहीं भगवे और हरे झंडे जो आज लेकर चलते हैं इनका यही रोल था जो आज है । महात्मा गांधी पर गोली तो बाद मे चली लेकिन उसके पहले भी उनका यही रोल रहा, कांग्रेस की मीटिंग भंग करना और गांधी पर कीचड़ उछालना ।

हमें गर्व है, हिन्दुस्तान दुनियाँ की चौथी फौजी ताकत है । छोटे-छोटे लोग, हरे-पीले पीले झंडे वालो के छोटे-छोटे दिमाग, अंग्रेजो के सहायकों का देश की स्वाधीनता के प्रति जो रवैय्या रहा है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा । स्वाधीनता संग्राम में उनका किरदार रहा है । और जो लोग जेल से माफी मांग कर आए है, उनके बारे में अगर राष्ट्रपति जी ने यह कहा होता कि जो लोग मुखबिर हुए है, अंग्रेजों सरकार से जेल से माफी मांग कर आए हैं, उनको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा तो मैं उसका स्वागत करता । जिन लोगों ने जनता पर डंडे बरसाए, जिन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया, हैरानी है, वह भी आज चुनाव लड़ते हैं ।

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : आप विधेयक लाएं, हम लोग, हम जनसंघ वाले उसका समर्थन करेंगे ।

श्री शशि भूषण : चोर की दाढ़ी में तिनका । मैने इनका जिक्र तक नहीं किया । मैं यह कह रहा हूं कि जो लोग हिन्दुस्तान की जनता पर कोड़े चलाते थे, हिन्दुस्तान की जनता जिन के नाम से नफरत करती थी, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में रुकावट खड़ी कीं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नही होना चाहिये—

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : आप क्या करते रहे है ?

श्री शशि भूषण : मै चार साल जेल मे रहा हूं । तुम्हारे महान नेताओ की तरह माफी माग कर नही आया ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : चोरी के इल्जाम मे ?

श्री शशि भूषण : जब हम जेलो मे जाते थे तो ये टोडी यही कहते थे कि चोरी डकैती के इल्जाम मे गए हैं यह इनका रोल रहा है । ये अंग्रेज सरकार की खुशामद किया करते थे—

अच्छा होता अगर इस बात का जिक्र राष्ट्रपति जी ने किया होता ।

श्री फूलचन्द वर्मा · आप प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाए, हम समर्थन करेगे ।

श्री शशि भूषण : मै लाऊंगा कि जो लोग अंग्रेज सरकार के मुखबिर रहे, हिन्दुस्तान की आजादी के रास्ते में जिन्होंने रोड़े अटकाए उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नही होना चाहिये और आप समर्थन दें ।

सैनिक शक्ति की दृष्टि से हमारा देश दुनियाँ की चौथी ताकत है । हमें अपने देश पर गर्व है । लेकिन कुछ लोगों को हमारे देश की बड़ी बड़ी योजनायें नजर नहीं आती हैं । उनको भाखड़ा और बोकारो

में अंगारों के ढेर नजर आते हैं । वे लोग देश को साम्राज्यवादी आंखों से देखते हैं। वे समझते हैं कि देश में खंडहर ही खण्डहर हैं और देश में अग्नि-वर्षा हो रही है, देश में कहीं शान्ति नहीं है ।

हम ने अपने देश में प्रजातंत्र के तरीके को अपनाया है । लेकिन ये लोग एम० एल०एज० का घेराव करने को प्रोत्साहन देते है । अगर यह तरीका अपनाया जाने लगा तो फिर प्रजातंत्र कैसे चल सकता है ? कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जिस का घेराव नहीं किया जा सकता है ? आज जो गुजरात में हो रहा है, वह देश भर मे हो सकता है ।

श्री जयप्रकाश नारायण जैसे नेता गुजरात मे विद्यार्थियो से कहते हैं कि जैसे वे 1942 के आन्दोलनों के समय स्कूलों, कालजों से बाहर निकल आये थे, वैसे ही वे अब भी बाहर निकल आयें । पुराने लोग इस सदन मे बैठे हुए हैं । उनको पता होगा कि श्री जयप्रकाश नारायण 1942 के आन्दोलन से पहले ही गिरफ्तार हो गये थे, और वह मार्च, 1943 मे हजारीबाग जेल से निकले । उस बीच मे पूरा आन्दोलन खत्म हो गया था । तब फिर उन्होंने 1942 के आन्दोलन में क्या किया ? वह खुद उस आन्दोलन मे मौजूद नही थे, वह उस आन्दोलन के नेता नही थें, लेकिन वह विद्यार्थियों को 1942 के आन्दोलन का हवाला देकर स्कूल-कालेजो से बाहर आने के लिए कहते है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है । श्री जयप्रकाश नारायण इस हाउस में मौजूद नहीं है । वह अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं । लेकिन माननीय सदस्य उनपर आरोप लगा रहे है । मै इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं ।

श्री शशि भूषण : अगर श्री जयप्रकाश नारायण हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र पर चोट करेंगे, तब हमें तथ्यों को बताना पड़ेगा । उन्होंने आर० एस० एस० की शाखाओं में हिस्सा लिया है । उन्होंने जनसंघ की विद्यार्थी सभाओं में कहा है कि विद्यार्थियों को स्कूल कालेज छोड़ कर आन्दोलन में हिस्सा लेना चाहिए ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Will he yield for a moment?

SHRI S. A. SHAMIM : May I defend J. P. Narain? He is only quoting his statement.

PROF. MADHU DANDAVATE : I sought his permission to intervene and he has yielded. He can quote Jaya Prakash Narain's statement. But while doing it, he referred to his past. Let me humbly point out to Shri Shashi Bhushan that a former Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru, had also acknowledged that Jaya Prakash Narain played a glorious role in the 1942 movement. Shri Shashi Bhushan may reject it for his own political ends, but let him not refer to his past like this.

श्री शशि भूषण : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण से व्यक्तिगत तौर पर मेरा विरोध नही है । लेकिन माननीय सदस्य को पता होगा कि श्री जयप्रकाश नारायण 1942 के आन्दोलन के समय जेल के अन्दर थे । जब वह हजारीबाग जेल से भागे, तो वह आन्दोलन खत्म हो चुका था । तो वह उस आन्दोलन के नेता कैसे हो सकते हैं ! उसके नेता विद्यार्थी थे ।

उस समय जिन झंडों को ले कर ये लोग साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए चले थे, उन्ही पीले झडों को लेकर ये लोग आज गुजरात मे घेराव करते हैं और यह प्रयत्न करते है कि इस मुल्क में प्रजातन्त्र खत्म हो । आखिर प्रजातन्त्र किस के लिए है ? हिन्दुस्तान के अधिकतर लोग गरीब हैं । ये व्हाइट-कालर को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देते हैं ।

[श्री शशि भूषण]

और उन को अधिक से अधिक पैसा देना चाहते है, जब कि ग़रीब लोग भूखो मर रहे हैं। अगर इस विषमता को दूर करने, और गांवों और शहरों के बीच के फ़र्क को कम करने, का प्रयत्न किया जाता है, तो कहा जाता है कि प्रधान मंत्री गलत काम कर रही है।

आज हमार देश मे हजारो किस्म के कपडे बनते है, जिस की वजह से देश के भूमिहीन मेहनतकश और दूसरे गरीब लोगो को कपडा नही मिलता है। इस लिए जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में सिर्फ पाच या दस किस्म के कपडे बने, ताकि देश के ग़रीब लोगो को कपडा मिल सके।

इसी तरह देश मे जमीन का बंटवारा ठीक होना चाहिए और एडल्ट्रेशन, ब्लैक-मार्केटिग और करप्शन करने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर इस बारे मे देश में जागृति हो, तो फिर यहा ये भगवे और हरे झंडे नजर नही आयेंगे। (व्यवधान) देश के गरीब और फटे-हाल लोग काग्रेस के समर्थक है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि शहरो का हिस्सा काट कर गरीबो को दिया जाये। इस क्रान्ति के लिए हमे तैयार रहना है। अगर जरूरत हो, तो एडल्ट्रैशन, ब्लैक-मार्केटिग और करप्शन करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए सरकार को इमर्जेन्सी पावर्ज लेनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी, तो सारा देश इस मे सरकार का साथ देगा। अगर दो तीन हजार ब्लैक-मार्केटियर्ज को गिरफ्तार कर के सड़को पर से निकाला जाये, जेल भेजा जाय, तो मै दावे के साथ कहता हूं कि तब कांग्रेस को कोई हिला नही सकता है। ये विरोधी जो उन के मददगार है, उन से डरने की जरूरत नही है।

आर० एस० एस० जैसी साम्प्रदायिक सस्थाओं पर बैन लगाना भी बहुत जरूरी है, वर्ना आज गुजरात मे जो हालत है, वह सारे देश में हो सकती है। अंग्रेज साम्राज्यवादी तो ऐसा करते ही क्यों? लेकिन आज इस सरकार को साम्प्रदायिक सस्थाओं पर बैन लगाना होगा। आज देश को सामाजिक क्रान्ति के लिए आगे बढ़ना है। उस क्रान्ति को कोई रोक नही सकता है। यह जमाना उस मे रोडा अटकाने वालो का नही है जिनके झडे यू० पी० मे हार रहे है और सारे देश मे हारेंगे।

SHRI H M PATEL (Dhandhuka): Mr Deputy-Speaker, Sir, the President's Address, to my mind, was platitudinous and deceptively frank. This becomes obvious if I quote one sentence from his Address where he says

"Supplies to deficit areas and vulnerable sections of society can be maintained through the public distribution system only if there is adequate procurement of graines."

Then he proceed "to impres upon the State Governments, with all the earnestness at my command, the importance of achieving procurement targets" He says that "it has to be realised that the Central Government can distribute only as much quantity as the State Governments procure and make available to it"

It would seem as if he is stating something that is obvious. And yet, in reality, he is suppressing all manner of things which need to be brought out. Does he not realise that the public distribution system failed and failed only because it is extremely inefficient?

The wheat trade was taken over without realising that the take over of wholesale trade means accepting responsibility for retail distribution. All the arrangements were to be made by the public distribution machinery. Not doing that resulted in suffering for the vulnerable sections of our society in whose interest it was stated that wheat trade was to be taken over. It is those very people who suffered because of the inefficiency of the public distribution system. It is they who could not get

wheat and if they got it, they got wheat at higher prices. Not only that; the country's economy as a whole also suffered because this take over led to a substantial general increase in prices.

With regard to procurement machinery I submit that procurement is inefficient, not because the State Governments are necessarily inefficient or unwilling. Procurement can be satisfactory only if the farmers are offered a reasonable and remunerative price. Unless you do that how can you expect the farmers to come forward and give what they have produced, at a loss. It is not realised that the cost of production of wheat in Punjab is substantially lower than the cost of production of wheat in say, Gujarat; the cost of production varies from State to State. Normally when price fixation of industrial products is undertaken, you proceed on the basis of the cost of production. But when it comes to agricultural products, this basis is not adopted. Totally different considerations come into operation. You say that if higher prices are paid to farmers—higher means adequate or reasonable price which even the Government would concede is reasonable—it would result in higher cost of living index and the urban population would have to be given higher dearness allowance. What happens then to agricultural labour? Is it never to be considered that the agricultural labour should also get a reasonable remuneration and the farmer also must get a satisfactory remuneration? You want to be unjust to the farmer and you expect the procurement machinery to function efficiently?

The Economic Survey placed on the Table of the House two days ago refers to this particular problem which faces the Government but the Government refuse to face it because the urban population, the wage earners are more organised and more vocal sections of society whereas the agricultural labour as well as the agricultural producer are disorganised and are unable to make their voice felt. This, I say, inspite of the fact that time and again reference is made to agricultural lobby and agricultural kulaks and so on, everything unpleasant that can be said about the farmers is said here. It is on agricultural prosperity that the prosperity of the country depends.

I would come back to the public distribution machinery. The efficiency of public distribution machinery can also be judged from another angle. I often wonder if the Agriculture Minister and his Ministry ever put themselves a few soul-searching questions. Whenever you buy anything from fair price shops or ration shops, the foodgrains that you obtain from them are of extremely poor quality and, often, unfit for human consumption. These were put on the Table a couple of days ago. How is it that the foodgrains distributed through fair price shops or ration shops are of such extremely poor quality whereas if you buy foodgrains in the open market, you get foodgrains of good quality.

Where do the foodgrains which are distributed through fair price shops come from? They are procured from the farmers; they are procured from the producers. They are perfectly good quality foodgrains at the time of procurement. What happens thereafter It is because of faulty storage, careless storage, indifferent storage, that the foodgrains become unfit for human consumption by the time they are released for distribution through fair price shops. Could there be anything more destructive? Can we conceive of more culpable, criminal than the wastage of foodgrains entirely due to inefficiency on the part of either the Food Corporation of India or on the part of which every wing of the public distribution machinery is responsible for it? This should never happen.

Sir, you will be interested to know that as much as 20 per cent of the country's agricultural production, the foodgrains, is lost through bad and indifferent storage. Why should that be allowed? Why is this degree of inefficiency allowed? This shall certainly never happen where the Government accepts the responsibility for both pro-

[Shri H. M. Patel]

curement on a monopoly basis and distribution also on a monopoly basis.

Now, I would like to make a brief reference to Gujarat. Already, some references have been made to the conditions obtaining in Gujarat. I would like to say with utmost emphasis possible that it is time the Government made up its mind that it is not desirable to allow things to drift any longer. The extent of hardship to ordinary men and, particularly, poor men, who earn and who live on daily wages is unimaginable. He suffers incredibly when cities and towns in which he lives and works, curfews are imposed. There is no work for them while the curfew lasts and, when the curfew is lifted, they have no money, no resources, to buy foodgrains and other essential articles necessary for keeping body and soul together. It is a matter of wonder to me how these people have managed to survive for such a long peroid during which Gujarat has now been suffering, undergoing—this agony has now gone on for over six weeks, indeed by now almost to two months. And yet no effective steps are being taken for the restoration of law and order.

Law and order is the responsibility of Government : since the President's rule has been ushered in in Gujarat, it becomes the responsibility of the Government of India. They must see to it that law and order is restored within the shortest possible time. It is a matter again for wonder that a Congress Government, with a strength of 114 in a House of 168, was unable to administer the State, was unable to maintain law and order in the State; and despite such a large majority, the Government of India had to intervene and President's rule had to be ushered in because the State Government had failed to maintain law and order. President's rule can be justified only if the law and order which has ceased to be in the State is restored as quickly as possible—the reason for which the President's rule has been brought in— and thereafter maintained in a continuous manner. I think, this is something which is incumbent on the Government, and I would strongly urge the Prime Minister to make up her mind as to the course of action that she should take in order that law and order is restored in the State within the shortest possible time. If she or her government cannot do this, then it seems to me that they are unfit to govern.

श्री रुद्र प्रताप सिंह (बाराबकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मै आप का हृदय से आभारी हू, आप ने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत और अनुमोदित हुआ है, उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है।

मान्यवर, मैंने अपने पूर्ववक्ताओं के भाषणो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, विशेष रूप से सम्मानित श्री वाजपेयी जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास किया। मान्यवर, लोकतन्त्र की बात करना और बात होती, परन्तु लोकतन्त्र के आदर्शों, लोकतन्त्र के मूल्यों के अनुरूप आचरण करना और बात है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय पर जिन विरोधी नेताओं और सम्मानित सदस्यो ने जिस प्रकार का आचरण किया था, उसे भारत ने ही नही पूरे विश्व ने देखा और समझा। मै यह कह सकता हू कि उस समय केन्द्रीय कक्ष मे लगे हुए राष्ट्र के महान नेताओ का चित्रों के मूक नेत्रों मे भी आंसू आ गये होंगे—उन के उस कारनामे को देख कर। उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न की गई, मै समझता हूं कि उस से भारत की संसदीय प्रणाली, भारत की ससद और भारत का अपमान हुआ है। जिस तरह का आचरण उस दिन इन विरोधी नेताओं और माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया, उससे मै समझता हू—भारत की ससद के भारत, के गौरव का, गरिमा का अपमान हुआ है।

यहां अभी इस बात की चर्चा की गई कि लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों में हमारे दल ने जनता को जो वचन दिये थे, उन्हें पूरा नही किया गया। मै

हूं —भारत के संविधान का 24वां संशोधन कर के हम ने विश्व को दिखा दिया है कि हम ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिस से भारत में समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राजा-महाराजाओं के प्रीवी-पर्स और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर के भारत की धरती पर राजा और रंक को समान नागरिकता प्रदान की है। साथ ही साथ हम ने देश भर में भूमि सुधारों के कार्यक्रम को आगे चला कर देश में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास किया है—इन सब बातों को उन्हें ध्यान में रखना होगा। यह भी सही बात है कि आज देश की जनता इस बात को बड़े विह्वल हो कर देख रही है कि शीघ्र से शीघ्र हम भारत में शहरी सम्पत्ति की सीमा का विधेयक लायें। भारत की जनता चाहती है कि शीघ्रातिशीघ्र चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक लाय और हम विरोधी दल के नेताओं को बताना चाहते हैं और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में हम दोनों विधेक अवश्य यहा लायेंगे।

श्रीमन्, यहां पर यह बात भी कही गई कि हमारी उपलब्धियां क्या है ? मै उन्हें बतलाना चाहता हूं—सन् 1971 के पश्चात् जिस प्रकार से अतिवृष्टि और अनावृष्टि का प्राकृतिक प्रकोप आया, नवीन बंगला देश के उदय के समय शरणार्थियों का जो भार पड़ा उन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद सम्पूर्ण भारत में काश्मीर से लेकर केरल तक और असम से लेकर गुजरात तक जिस प्रकार से विकास कार्य होते रहे हैं, हम समझते है कि यह संसार का आठवां आश्चर्य है।

मान्यवर, यह प्रसन्नता की बात है—भाषण मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जमाखोरी तथा उत्पादन के संचालन व वितरण के कार्यों में रोड़ा अटकाने के प्रयासों के खिलाफ़ सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। इस बात के लिये हमें सरकार को बधाई देनी चाहिये। आज देश में जो मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है, जमाखोरी, चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मिलावट और भ्रष्टाचार है, इन का मूलकारण देश के पूंजीपति हैं और उन पूंजीपतियों के संरक्षण विरोधी दल हैं और हमारे बड़े अफसरान हैं—इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये, आवश्यकता पड़ने पर तथा उचित समझा जाय तो राष्ट्र द्रोह करनेवालो को जो दण्ड दिया जाता है, इन लोगों के लिये भी उस दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की आ गई है कि हम इस प्रकार का विधेयक लायें जिस में ऐसी व्यवस्था हो कि एक परिवार के पास इस से अधिक सम्पत्ति नहीं होगी, इस से अधिक आमदनी का साधन नहीं होगा। हमें इस बात की सीमा तय करनी होगी, गारण्टी देनी होगी कि एक परिवार की कम से कम क्या आय हो, कम से कम क्या सम्पत्ति हो—तब हमारी समाजवाद की कल्पना सही मायनों में साकार हो सकेगी।

हमे विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व मे हम जिस समाजवाद की कल्पना करते है, उस का स्वरूप मूर्तिमान अवश्य होगा—यह मै विरोधी नेताओं को बताना चाहता हू।

एक और विशेष बात है—हम समाजवादी नीतियों के लिये, देश के अन्दर सामाजिक, आर्थिक विषमताओं को मिटाने के लिये, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को मिटाने के लिये, नाना प्रकार की जो कठिनाइयां है उन को दूर करने के लिये, जो कदम उठाते हैं, जो नीति हम बनाते हैं, आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि 75 फीसदी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उस का विरोध करते हैं, हमारी नीतियों को कार्यान्वित नही होने देते। जो लोग भूखे हैं, नंगे हैं, अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये जिन के सामने

[श्री चन्द्र प्रताप सिंह]

अभाव है, वे कुछ हद तक क्षम्य हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिन के पास अथाह दौलत है, बड़े वेतन पाते हैं, बंगलों में रहते हैं, उन को क्षमा नही किया जा सकता । इस लिये इस बात की आवश्यकता आ गई है कि आज हम अपने संविधान में संशोधन करें और सचिवों से एक्ज़िक्यूटिव पावर्स छीन कर अपने मंत्रियों को दे और उस में इस बात की व्यवस्था करें कि हमारे मंत्री जिस सम्बन्धित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को जन-विरोधी कार्य के लिये निलबित या निष्कासित करें, उस को न्यायालय मे जाने का अधिकार नही होना चाहिये । तभी हमारी अकाक्षाओं की पूर्ति होगी ।

आज यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी विदेश नीति शिखर की ओर अग्रसर हो रही है । हमारे महान मित्र देश सोवियत रूस के महान नेता श्री ब्रेझनेव की भारत यात्रा से हमारी मैत्री प्रगाढ़ हुई है और हम समझते हैं कि आपस में सहयोग के नवीन द्वार खुले हैं । साथ ही साथ अभी हमारे मित्र पाकिस्तान ने बंगला देश को जो मान्यता दी है, इसमे भारत, पाकिस्तान और बगला देश के सम्बन्ध और अधिक दृढ होंगे और मित्रता प्रगाढ होगी । हम यह भी आशा करते है कि भारत की सफल विदेश नीति के कारण हमारे पड़ौसी देशों से मित्रता बढेगी और जो विकासशील देश है, हमारे मित्र अरब देश है, उन के साथ जो हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध चले आ रहे हैं उन सम्बन्धो में निरन्तर रूप से वृद्धि होगी ।

इसके साथ साथ मै यह भी कहना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश मे अभी जो विधान सभा के निर्वाचन हुए उसके सम्बन्ध में वाजपेयी जी ने बहुत कुछ कहा । मेरे पास समय नही कि मैं बहुत कुछ कह सकू लेकिन आपकी अनुमति से थोड़ा सा कहना चाहता हू । उन्होने कहा उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनावों में श्रीमती गांधी ने यह किया, श्रीमती गांधी ने वह किया लेकिन मै वाजपेयी जी को बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया । वहां पर उन्होंने जो किया है उसको भारत तथा उत्तर प्रदेश की जनता कभी क्षमा नहीं कर सकती है । उत्तर प्रदेश में जितने प्रतिक्रियावादी दल हैं--जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय क्रान्ति दल इत्यादि---उन्होंने जिस तरह से पूजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव मे बहाया है उसको हम बयान नही कर सकते हैं । सारा का सारा चुनाव इन पार्टियो ने पैसे के बल पर लड़ने की चेष्टा की है । यह पार्टियां पूजीपतियो के साथ साठ-गाठ करके देश मे अराजकता उत्पन्न करना चाहती है, इस देश मे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती हैं जिससे इस देश में समाजवाद लाने का हमारा जो संकल्प है उससे हम हट जायें । साथ साथ इन्होंने जो सबसे गलत काम किया है वह यह है कि लोकतन्त्र और भारतीय सस्कृति की आज बात करने वाले इन लोगो ने जनता के बीच में हिन्दु-मुसलमान की बात की है । मै इन्हें बताना चाहता हू कि भारतीय संस्कृति का अर्थ है हम विश्व के समस्त धर्मो का समान रूप से आदर करते है और यही हमारी भारतीय सस्कृति है । भारतीय सस्कृति का अर्थ यह नही है कि हम हिन्दू मुसलमान अथवा हिन्दू धर्म व इस्लाम धर्म के नाम पर लोगो मे अन्तर करे । हमारी सस्कृति समस्त धर्मो का समान रूप से आदर करती है और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बात को मानती है । यह लोग जब जाति, धर्म व हिन्दू मुसलमान की बात करते है तो भूल जाते है कि भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है । हम तो वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते हैं । हम कहते है कि भारत ही नही, सारे विश्व मे जितने लोग है सभी हमारे भाई है । आज यदि भारत मे नही, इराक या ईरान में किसी लड़की का अपमान होता है तो हम समझते हैं हमारी ही बहन या लड़की का अपमान हुआ है । इसलिए वाजपेयी जी को समझना होगा कि भारतीय सस्कृति क्या है ?

मैं यह कह रहा था कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो सबसे गलत काम किया है कि वह यह कि इन्होंने चुनाव में जातिवाद और सम्प्रदायवाद का नाम दिया। यह बात किसी भी देश के लोकतन्त्र के लिए एक खतरनाक बात है। हमारे वाजपेयी जी यहां पर लोकतन्त्र की बात करते हैं तथा इन्होंने व अन्य विरोधी दलों ने उस चुनाव में जो जातिवाद तथा सम्प्रदाय का सहारा लिया उससे लोकतन्त्र की जड़ें हिल गई हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए इन लोगों ने वहां पर जो कुकर्म किए हैं उनकी जितनी भी निन्दा की जाये कम ही होगी। जहांतक हमारा प्रश्न है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। आज और कल के परिणाम बता देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ है। यदि जातिवाद, सम्प्रदायवाद व धन के दुरुपयोग के कारण हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हार भी गए तो भी हम अपना रास्ता बदलने वाले नहीं हैं। समाजवाद लाने का जो हमारा मकसद है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे तथा जो यहां पर सामाजिक व आर्थिक विषमतायें हैं उनको दूर करेंगे। हम चुनाव हार सकते हैं पर जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद का सहारा चुनाव में लेने का दृढ़ विरोध करते रहेंगे।

अन्त में मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि पूंजीपतियों के द्वारा देश की 55 करोड़ जनता के साथ जो नाना प्रकार के शोषण, अत्याचार व भ्रष्टाचार हो रहा है तथा चुनावों में जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए विशेष रूप से सरकार को अपनी रीति नीति अपनानी होगी।

आखिर में यह कहकर समाप्त कर रहा हूं :

> यह ऊंचे महल जो नजर आ रहे हैं
> नजाकत पर अपनी इतरा रहे हैं।
> जरा इन के गमलों के फूलों को सूंघो
> खूने गरीबां की बू आ रही है।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North-East): Before I speak, Mr. Deputy-Speaker, I would like to draw your attention to the fact that apart from the Minister of Parliamentary Affairs whose responsibility is very limited, not one Cabinet Minister has been in attendance since 2.30 P.M. when you took your seat.

Sir, this is disrespect of a House of an egregious character. I expect you, on behalf of this House, to convey the disrespect of this House in regard to this business. This is a submission which I make with great seriousness. I have been accustomed since 1952 to address this House when Jawaharlal Nehru and the whole array of Cabinet Ministers would be ready to listen to and participate in the discussion.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): This is disrespect not only to this House but to the President himself because it is his Address which is being discussed.

SHRI S. A. SHAMIM : They made him to read that Address but now they are not present here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I hope the Minister for Parliamentary Affairs will take note of this.

SHRI H. N. MUKERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have had the ritual performance by our President which is all the more pitiful on account of the harrowing living conditions of our people to-day. I have a feeling and this has been echoed in this House repeatedly by several Members that this senseless ceremonial which is a sort of feudal relic should be discarded because, except for this opportunity of getting the Government show something of its answerability, this occasion is not called for. We could have this debate in a more substantial manner without the panoply and the semi-feudal paraphernalia of the President's Address ceremonial. It is, perhaps, because of this Government's adherence to the idea of a feudal concept that we recently had the phenome-

[Shri M. N. Mukerjee]

tion of this country giving an official welcome to representatives of a defunct monarchy, a dynasty, which is no longer in the historical picture, the Hapsburg dynasty of Spain, which is now ruled under the republican order, of General Franco as the head of State and the External Affairs Ministry had the gumption to put out a note for public consumption that because Gen-Franco has declared in some statement in Spain that the prince and the princess would be the head of State after his demise, therefore, they should be treated with royal honours. And when they came to the Republic of India, they were treated with a consideration which only shows that perhaps this country also has a certain weakness for that kind of administration. This partiality for Spain is something which I just cannot understand. But, this shows why it is that the Government, in so many respects, even in the sphere of foreign policy, has cold feet mainly because the people who matter in the Ministry concerned are brought up in a fashion which is absolutely out of tune with the conditions of life of our country.

The President has chosen to juxtapose high prices and scarcity of commodities with "strikes, *bandhs* and unrest" as the cause of what is called "so many hardships." Strikes, *bandhs* and unrest are not the cause but the result of the sufferings caused by high prices, unemployment, profiteering and plunder by the top-run sharks whose interests are rendered to by the Government of the day. It is a pity that there is no realisation of the dominant reality of to-day, which is sweeping mass discontent, the explosive exasperation of our people, which found expression, particularly in Gujarat, which, normally, is so meek and mild. But, in spite of all this, we find on the part of Government a kind of lack of seriousness, to put it in a very civilised manner.

It is only natural for our masses to be angry and indignant and it is in that way the spirit of our people has been exhibited. It is a wrong sort of thing that the Government has gone on in the manner that it has done so far. We find, for instance, that in Bombay, India's bourgeois paradise, the proud show-piece of India's "socialistic" advance. We had the peculiar phenomenon of the Government of a State joining hands with Shiv Sena and starting a racket which is disgraceful. It is common knowledge how the Shiv Sena has had a fascist record throughout and it is nothing sort of a calumny that the Government of the state had joined hands with the Shiv Sena in that way. The people of Bombay, have elected a Member of my party who, ought to have taken part in the debate—I am taking her place—but who, unfortunately, is not here as she is in a hospital, and her victory shows that the people are alive to the danger in Government's policy. The Government behaves in a manner which is disgraceful. I say it is disgraceful because we have the Commissioners of Linguistic Minorities and that sort of thing, and we are supposed to have discussed the reports of the Commissioners and so many other things relevant to the linguistic minorities. And Bombay which is a cosmopolitan city like Calcutta is a place where people from different States have a right to exist and work for their living, but on the score of jobs for the children of the soil, all kinds of depradations are taking place. I have here certain documents which show that the demand of the Shiva Sena for 80 per cent of all jobs in all kinds of establishments, factories, banks and offices etc. to be given to people who are Maharashtrian-born, is supported by the Government; the Government writes letters officially to the All India Manufacturers' Organisation who distribute these letters to their members and they are told to follow this rule.

The Kerala Assembly had even passed a resolution in regard to the kind of disgraceful thing which happened in Bombay. But where are we if in the cosmopolitan city like Bombay we are told that only Bombay people would get their employment? Sir, I come from Calcutta which at least can claim possession of a shining sense of public spirit; we have never had people who

stand for parochial and communal considerations to have even a seat not only in the city of Calcutta but from anywhere in the districts, to the legislature of my State. But here in Bombay, because of the Government of Maharashtra having joined hands with Shiv Sena we discover this kind of enormity taking place.

I want the Prime Minister to take very serious note of this matter and tell us on this matter that something very drastic is going to be done in regard to all the enormities which are being perpetrated by Mr. Naik and Mr. Rajni Patel and all that unspeakable crowd operating in Bombay, that they are brought to book and something is done to stop this nonsense.

There is no doubt that in Bombay, for instance, we find such things as for instance in the *Blitz*, a paper which is devoted to the Prime Minister, the last page run by Mr. Abbas where he refers to a phenomenon which is to the effect that the State Bank of India's multi-storeyed mansion has had one floor reconditioned and furnished in Babylonian luxury conditions in order that it may serve the sensibility of a man called Mr. Talwar who happens to be the chairman or the managing director of the State Bank of India. Rs. 15 lakhs were spent according to Mr. Abbas's 'last-page' report where he makes an appeal to the Prime Minister that this kind of ostentatious conspicuous consumption at a time when people are suffering is something so vulgar and something so indecent that I do not understand how man like Mr. Borooah who now has come to represent the Cabinet can stick this kind of indignity being inflicted on our people. Rs. 15 lakhs spent on furnishing an entire floor of the building of the State Bank of India, a common talk in Bombay these days.

In Bombay, we read in this paper again that hair-dresser from London was brought by a person who got married and at his wedding which cost Rs. 20,000, for the London hair-dresser's journey, who might even have been a smuggling agent, Ministers of State were present just as in the case of the Mohita case last year, where Bombay Ministers flocked like people ching for good food at the expense of one of the sharks in this country. This is the sort of life that our people live and this is the context in which we find another paper again ardently devoted to the Prime Minister, a weekly called *New Wave* where there is a letter sent to the "respected Prime Minister" by a young student of Calcutta who was preparing his M.Sc. thesis that he was on suspicion of being an ultra-revolutionary beaten up, taken by the police to Kharagpur some 70 miles out of Calcutta, then his limbs were broken and he was thrown into the street where some kindly people helped him to come back to his home after a two-day journey. He writes to the Prime Minister : 'Will you please help me because I have nothing to do with it? I was on suspicion treated by the police in this fashion'.

What kind of country do we live in? We hear repeatedly reference to the Research and Analysis Wing which seems to have the run of the place with large resources of money, perhaps from secret service sources. I am not going to ask for detailed information about secret service, but what is this about the Research and Analysis Wing? Let us have some information. Why is it that more than 10,000 prisoners are there in West Bengal alone, in Andhra and other places on the allegation of being ultra-revolutionaries. So many prisoners are being treated so shabbily that one thinks it a disgrace to call it a democratic country. This is the contradiction as far as this Government is concerned. Just as in the sphere of foreign policy, they fete the Spanish Crown Prince and Princes—he is no crown prince whatever—so in regard to internal policy, we find this sort of thing going on and affluence flaunting itself while as far as people's rights are concerned, the rights are absolutely disregarded in a fashion which is utterly disgraceful.

I would certainly insist that the Prime Minister explain something about the Research and Analysis Wing and give us to understand that the enormities which are taking place in so far as political prisoners and detenus are concerned would be put an end to without any further delay.

15.57 HRS.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

As far as affluence is concerned and the sort of exhibition of luxury that goes on, I think it is time, Mr. Chairman, whom I am happy to see presiding over our deliberations, that even though we may not like the expression 'cultural revolution' which has been used by China, we need something like a cultural revolution.

PROF. MADHU DANDAVATE : It is a very good term.

SHRI H. N. MUKERJEE : It is a very good term even though it may have a connotation which may not always be as good as we wish it to be.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The ruling party has undergone it.

SHRI H. N. MUKERJEE: In the Plan, I find there is some talk—Shri Mishra knows a good deal more about it—of reducing by about 4 per cent the consumption of the top 30 per cent of the population. But as far as implementation is concerned, this is beloney. In the past three years, we find the output of necessities like sugar, food, vanaspati stagnating and that of millmade cloth actually dwindling while production of refrigerators, air-conditioners and motor cars has more than doubled. We are having a great deal of synthetic fibres, expensive fabrics and superfine cloth. Dams and factories can wait but fancy dwelling in Bombay and Delhi must come first. Farm implements must wait but small cars, Maruti or no Maruti, must come earlier than farm implements and public sector commercial vehicles. Baby food is expensive and unavailable. The price was Rs. 9 per kg. in November 1972. It was more than Rs. 20 per kg. in November 1973. There are no attempts to increase indigenous milk production while in the last ten years, beer and ale production has shot up from 5.4 million litres to 38.1 million litres—7.1 times. Cadbury chocolates, food for the affluent classes who do not need it, who do want medication after gorging themselves with sweets they do not need—the Cadburys make money. They came with Rs. 5 lakhs as capital 25 years ago. They have sent back more than 50 times that amount. They are repatriating every year more than Rs. 20 lakhs while I find, according to a government reply to a question yesterday, that 12,000—14,000 children go blind because of the lack of sufficient vitamin A. This is the kind of picture we see, this is the kind of country we live in.

16.00 HRS.

We hear tall talk, but in so far as the living conditions of the people are concerned, there is degeneration all over the place. In Bombay we have seen the Shiv Sena's enormity; in foreign policy, they are falling head over heels in love with the Crown Prince and Crown Princess of Spain who are no princes at all. Repression inside jails; repression outside jails as far as political opponents are concerned. And there is reliance only on the wave of support which had sent the Government to power with a massive majority.

I had said earlier, and I want to repeat it; assent is usually slow and difficult; it took the Prime Minister some time to reach the height of her target. From 1966 to 1969 was a difficult story of assent. We applauded her assent. We had given her all the assistance that she needed. Even today, if she behaves, we shall give her all the assistance she deserves. But descent can be quick, and when the people's anger is expressed in such a manner as in Gujarat and elsewhere, they should take the warning. The hand-writing is on the wall, and and if they do not learn the lesson of what is happening in the country today, if they remain compla-

cent, if they do not change their tactics qualitatively, then, they are riding the high horse no doubt today because they have power and money to back them, but they are riding for a fall, and if after such glory they fall, that fall would be like the fall of Lucifer, not to rise again.

I do not wish them to fall; because the alternatives are worse, but I do not wish this Government to console itsell that they are the lesser evil; to be the lesser evil is historically a destiny which no decent Government could conceivably welcome. That is the destiny which they are clasping now because they do not know what to do about it. And they have only a sense of guilt, which is why that they do not come and face Parliament, which is why they show an allergy to democratic procedure. That is why they do not want discussion of a sort which is the lifeblood of parliamentary activity.

I say, therefore, this Government has been warned, and they should listen betimes to the warning which has been uttered by the movement, the massive movement of our people. That is the lesson which I want to imprint, if I can, on their minds.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): Thank you very much for comparing with Lucifer. I thought you would mention Humpty-dumpty rather than Lucifer.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Mr. Chairman, Sir, since the Minister of Petroleum and Chemicals is here, let me first congratulate him—

SHRI S. A. SHAMIM : First thank Shri Mukerjee; otherwise, he would have been sleeping somewhere

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA : He was busy in Bombay High. Let me congratulate him for that, as we have struck oil in Bombay High. (*Interruptions*) I am one who believes that whatever God does is for our good. Sir, let the scarcity of oil which has come may also be the indirect grace of God and that we will become self-sufficient by developing our own resources in oil.

Sir, sometime back, we have been on and off referring here to the oil availability in Andhra Pradesh. Several teams have visited there. A Soviet team also had visited there and said that there is oil available in the Godavari-Krishna basin. But due to the lack of drilling facilities it has not been exploited. So, I request that the Minister may keep this in his view and see that immediately a survey team is sent, a seismic team is sent there and then the exploration of oil as in the Bombay High is begun in Andhra Pradesh also.

As far as oil concession and deals with the oil-producing countries are concerned, I think we need not depend on it because it is ultimately the developed countries, because of the vast reources at their disposal, that will benefit and their people will benefit. Only with friendship and goodwill, we can get benefit from outside countries.

MR. CHAIRMAN : Are you speaking on the Motion of Thanks to the President or about the Petroleum Ministry ?

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA : The President has referred to the oil crisis in his address. I wanted to refer to this problem in the last part of my speech, but when I saw the hon. Minister, I was inspired to speak about oil in the beginning. I think that is more useful thing than abusing each other. Some concrete steps should be taken to develop the oil resources in our country.

Coming to President's Address I want to bring out certain truths. Naturally truth is bitter and I should not be misunderstood. The Bhagwat Gita says that what appears bitter in the beginning will be nectar in the end and what appears to be nectar in the beginning may turn out to be poison in the end. Today our whole attention is concentrated on the hardships and sufferings of the people. Naturally the President has himself given importance to this matter in his speech. We have expressed our sympathy to the people here and outside. The President himself has expressed sympathy for the hardships of the people.

[Shrimati T. Lakshmikanthamma]

Perhaps it is easy to do this. To show the way how to remove the difficulties and solve the problems is not that easy. The steps that we are taking in this direction are not forceful and effective. The President in his Address has given a number of reasons for the rise in prices. Are these reasons going to help us in solving the problems? यहां पर बहुत उपदेश दिये गये है। कल भी दिये गये हैं, परसों भी और आज भी। इस देश मे एक चीज जिसकी कीमत नहीं बढ़ी है वह उपदेश है। और मुफत मिलता है।

It is not even one and a half months since the kharif harvest was over in Andhra Pradesh. Even in surplus States like Andhra Pradesh prices have not come down. They are the same or perhaps more than what they were in May last. What is the reason for this? Whether it is a world phenomenon or not, it is the different matter. Has the Government understood that it is the result of the defective policies pursued in the matter. When a surplus State is made a free zone as our State was made very recently in our State and all the restrictions on internal movements of foodgrains are removed it helps the hoarders and smugglers to mop up all the stocks for profiteering at a later stage. I can understand if it helps the people of Maharashtra or Madras... *(Interruptions)*. I want to warn the Government of one thing. In a month or two even in a surplus State like Andhra Pradesh. prices will start going up. I want to know whether the Government is taking some action to stop a situation. Apart from the advice we give what is the solution.

It is a fact that procurement is essential. At a time when there is a bumper crop, we allow traders to deal in wholesale trade in foodgrains. But when there is some difficult situation, suddenly we think of some public distribution system. Is it posible to gear it up so suddently? The permanent measures should be taken to set right the public distribution system.

Some arguments are put forward that the kisan is not willing to part with his foodgrains. What have we done? At the time of agricultural operations, if you give him manure, chemical fertiliser, diesel oil, some of his requirements, I am sure, he will gladly part with his foodgrains.

It appeared in a part of the press—I do not want to mention the name—that one Central Cabinet Minister in a press encounter ascribed the failure of the procurement drive in a year of good harvest to the anger of land-owners against attempts to seize their land. He justified the opposition to land reforms by taking of the peasants attachment to his land, citing the case of his servant. Will this not demoralise us and sap our will to fulfil the promises that we have made to the people?

There is nothing wrong in our fundamental policy of taking over wholesale trade in foodgrains. The main difficulty is defective public distribution system. Are we whole-heartedly trying to implement it is the main thing? There are certain States whose actions have been helping the traders in making huge profits. What is the outcome? What is the result? By not following our policies wholeheartedly, having lack of faith, on the part of certain State Governments in our policies, by helping the black marketeers and profiteers, by not pursuing our policies, ultimately, our policies are crucified. The people lose faith in us; they say that we are not implementing our policies. The poor people are undergoing immeasureable sufferings and difficulties I feel, this is a bad sign, an inauspicious sign.

I would like to say a few words about the States. So much has been said about the States. My own State has suffered. We gave a lead; may be, we gave a bad lead. But that is a different thing. Yesterday, Mr. Dandavate was emotionally telling us about Bombay that whatever happens, Bombay shall not be separated. Why don't you have the same emotional feeling about my State?

In 1972, the people gave us a massive mandate. The people put us in power. Why? Because they felt that there should be stable Governments in the States and they expected that we will implement the promises given to the people. What

happened ? The Congress Governments, one after another, started falling, in Andhra Pradesh, in U.P., in Gujarat, in so many States . The people expected that we should implement our policies and the promises given to them. At the time of emergency, they said, "Like brave soldiers, we are prepared to fight and die." Are we prepared to do ? Instead of taking the challenge and fighting like brave soldiers, we have shown our back when these reactionary forces held us up and also compromised with them and allowed them to take a lead.

There is a story that in war we should never show our back. When the body of a young soldier comes home, the mother sees whether the bullet is hit at the back or the front. If it is at the back, the mother has contempt that her child was a coward, he has shown his back. We should not do it. Even in the beginning stages, when the anti-social elements and reactionaries started creating hardship and coming in our way, we started shaking. Why ? Why these days do we not hear speeches either from Ministers or from others about implementation of land reforms or ceiling on urban property ? In every State we are immersed in power politics and are going far away from our chosen path. It is high time for introspection and self-analysis.

It is not correct to say that weak States make a strong Centre. States are like the limbs of body. If the hand is weak, ultimately the body will become weak. If the leg is weak, we get paralysis and ultimately the whole body suffers. So, it is strong States that make a strong Centre It is a wrong argument to say that weak States make a strong Centre

MR CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA : Since you are presiding, Mr. Chairman, you are the protector of democracy. So, I appeal to you that it is a question of democratic system; it is not a question of party system; it is not a question whether Gujarat goes or Andhra Pradesh goes. It is a question of saving a democratic institution. People have given a massive mandate. If democratic governments cannot deal with the situation, can Padma Vibhushan Sarin deal with it ?

MR. CHAIRMAN : Why are you against Padma Vibushan so much ?

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA : If today we weaken our own democratic institution—when people have given such a massive mandate—then tomorrow how can you go to them and ask for help ? We have to set up certain fundamental values. I want to repeat the same thing which Mr. Morarji Desai has said. Certain values have to be set up, certain democratic values have to be set up. (*Interruptions*) This is not the way of setting up democratic values. The same thing may happen anywhere. Why should we allow these things ? It is the duty of every one of us, on this side or on that side, to maintain democratic institutions and set up certain democratic standards.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट में मेरा जो तजुर्बा रहा है उस की बिना पर मुझे यह एहसास हो रहा है कि पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंटरी सिस्टम और पार्लियामेंटरी तरीका-ए-कार इस मुल्क में रफ्ता-रफ्ता इर्रेलिवेंट बनता जा रहा है। मेरा यह एहसास राष्ट्रपति का एड्रेस सुनने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया। कल जब नये दौर के महात्मा—डा० कर्ण सिंह— यहां तकरीर कर रहे थे मारेलिटी, स्पिरिटुअलिज्म और वैल्यूज पर, तो मेरा यह विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गया कि इस मुल्क की जनता में पार्लियामेंट का ताल्लुक, उस का रिश्ता, कटता जा रहा है। हम यहां ज्यादा से ज्यादा एक नाटक करते हैं। सरकारी दल एक बात कहता है और आपोजीशन उस का विरोध करती है। अगर आपोजीशन कोई बात कहती है, तो सरकार को इस की मुखालफित करनी चाहिए, यह हमारा रोल रहा है। अब लोगों का एतकाद रफ्ता-रफ्ता पार्लियामेंटरी सिस्टम पर से उठता जा रहा है।

[श्री एस०ए० शमीम]

यहां पर अक्सर यह बात कही गई कि गुजरात में जो कुछ हुआ, यह इस वक्त मुल्क में हिंसा का जो दौर चल रहा है, उस का सबब यह है कि कुछ विरोधी दल इस सिटुएशन को एक्सप्लायट कर रहे हैं, कुछ एन्टी-सोशल एलीमेंट्स इस सिटुएशन को एक्सप्लायट कर रहे है ।

यह जानने की बात है कि क्यों हजारों की तादाद में लोग कानून तोड़ कर गोलियां खाने के लिए आते हैं, कर्फ्यू तोड़ते है, फौज का मुकाबिला करते है, पुलिस का मुकाबिला करते हैं, उस का कारण क्या है ? यह कोई शौक की बात नही है, तमाशा करने की बात नही है और जब नौजवान हमारे पालियामेंट्री सिस्टम पर विश्वास खो कर उस के बाद सीना तान कर गोलियां खाने के लिए आमादा हो जायें तो इस को आप अपोजीशन का कारनामा कह कर अपोजीशन को क्रैडिट दे रहे हैं । जिस काम का अहल अपोजीशन नही है आप उसको वह तगमा दे रहे है । अगर वाक़ई इस मुल्क मे अपोजीशन आज इतनी स्ट्रांग है कि वह गुजरात मे एक खामोश नही तूफानी इन्कलाब पैदा कर सकती है तो मै समझता हूं कि फिर तो कांग्रेस को यहा से उठ कर चले जाना चाहिए । लेकिन मैं समझता हू कि उन मे कांग्रेसी भी है, गैर-कांग्रेसी भी है, बदकिस्मती से उन का पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन मे विश्वास उठता जा रहा है । इस मे दोष किस का है ? मैं दोष सिर्फ हुक्मरां जमात को नही देना चाहता । मैं इस बात को कहना चाहता हू कि जम्हूरित की कदरों को पामाल करने के लिए, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन पर विश्वास खत्म करने के लिए अगर सरकारी जमात मुल्जिम है तो अपोजीशन भी बराबर मुल्जिम है । हम सब ने मिल कर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश कर के रख दिया । नतीजा यह है कि आज सब से ज्यादा कन्टेम्प्ट का मरकज़ जो है वह लेजिस्लेटर है, पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वह अपोजीशन को बिलांग करता है चाहे सरकारी जमात को । लेकिन यह कहने के बाद यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि इस में सब से ज्यादा दोष किस का है, सब से ज्यादा गाली किस को मिलनी चाहिए, सब से ज्यादा सजा किस को मिलनी चाहिए ?

27 साल इस मुल्क की हुकूमत आपके हाथ में रही । आज अगर गुजरात के लोगों का लावा इतनी जोर से उबलने लगा, आज अगर महाराष्ट्र में बेचैनी है तो सवाल है कि इस का दोष किस को जायगा ? आप कहते है कि भाखरा हम ने बनाया, बोकारो हम ने बनाया, इस मुल्क मे हम ने इतनी तरक्की की । उस के लिए आप दाद चाहते हैं । ताली चाहते हैं । लेकिन इस बात के लिए अगर आप को ताली मिल सकती है तो और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, हिंसा हो रही है, भूख है, भुखमरी है उस के लिए आप को गाली भी जरूर मिलनी चाहिए । आप यह कह नही सकते कि मीठा मीठा हड़प, उस के लिए ताली बजाओ लेकिन अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो वह अपोजीशन के सिर पर थोपो ।

सब से बड़ी बात वैल्यूज की है । सब से ज्यादा बातें उस मामले मे डा० कर्ण सिह ने की । वैल्यूज की बाते उन्होंने की । क्या वैल्यूज की बातें है ? गाधी जी इस मुल्क मे थे, जवाहर लाल नेहरू इस मुल्क मे थे । इस मुल्क मे करप्शन उस वक्त भी था, भूख उस वक्त भी थी, इस मुल्क में बेकारी उस वक्त भी थी । लेकिन एक विश्वास था कि गांधी जी एक आईडियल है, जवाहर लाल जी एक आइडियल है, ये कोई ऐसा समझौता नही कर सकते या कोई ऐसी कार्यवाही नही कर सकते जिस मे जनता का विश्वास खत्म हो जाय । लेकिन अब सब से बड़ी बात जो हो रही है वह यह हो रही है कि आप लोग जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं वह 27 वर्षों से कर रहे हैं इस बदकिस्मत मुल्क के ऐवान पर, आप हमारे आइडियल नही हैं । आप की

कोताहियों का नतीजा क्या हो रहा है ? यह अलग एक बात है, इस वक्त मुल्क में एकोनामिक स्फेयर में बड़ी गंभीर सिचुएशन है । यह घबराने की जरूर बात है । मुल्क में इस वक्त बेचैनी है, यह घबराने की जरूर बात है । इस के लिए परेशान होने की बात है । लेकिन सब से ज्यादा खतरा जो इस वक्त है, सब से बड़ी मुश्किल जो इस वक्त है वह यह है कि इन हालात को पैदा करने में हुक्मराम जमात और अपोजीशन मिल कर एक माहौल तैयार कर रही हैं जिस में सब से ज्यादा फायदा इस मुल्क के फिरकादाराना कम्युनल एलीमेंट्स को हो रहा है ।

मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त मुस्लिम लीग के मुहम्मद कोया या नये मुस्लिम लीग के कायदे आजम श्री सुलेमान सेट यहां नहीं हैं । वह यहां होते तो मैं जरा खुल कर बात करता कि हुक्मरां जमात की नाकामियों से फायदा उठा कर इस मुल्क में एक बार फिर 1945 और 1947 का सा एटमास्फैयर पैदा करने की कोशिश की जा रही है । मुहम्मद कोया साहब ने कल कहा कि वह मुस्लिम कम्यूनिटी को रेप्रेजेन्ट करते हैं और सिर्फ वह यह हक रखते हैं कि मुसलमानों की बातों को कहें । अगर हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने मुहम्मद कोया को यह हक दिया होता या श्री सुलेमान सैट को यह हक दिया होता तो आज मुसलमानों का इस मुल्क में वजूद भी नहीं होता । मुसलमानों का 7 करोड़ की तादाद में यहां रहना इस बात की जमानत है कि उन्होंने विश्वास किया है इस मुल्क की अकसरियती जमात पर, इस मुल्क के हिन्दुओं पर, उन सेक्यालुर अनासिर पर जिन्होंने 1947 के खूनी ड्रामे में भी कहा कि चाहे पाकिस्तान अपना मुल्क इस्लामी आधार पर बनाए लेकिन हिन्दुस्तान सेक्युलर इरादे पर कायम रहेगा और हिन्दुस्तान को सेक्युलर आईन दिया । उस वक्त मुस्लिम लीग के ये कायदे आजम जो आज सब्ज परचम ले कर मुरादाबाद; हैदराबाद और यू० पी० में फिर रहे हैं, उस वक्त इन का कहीं वजूद नहीं था । मुझे यू० पी० के हाली इन्तखाबात में कुछ इलाकों का दौरा करने का मौका मिला । मुझे हैरत है इस ऐवान में बहुत से लोगों ने बुराई की सरकार की कि उन्होंने शिव-सेना के साथ समझौता किया है लेकिन मैं इल्ज़ाम लगाता हूं, मेरा जार्च है इस सरकार पर कि इस मुल्क में इस हुकूमत ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर के, केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर के इस मुल्क की एकता को, इस मुल्क की सेक्युलर फोर्सेज़ को सब से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है । यही वजह है कि श्री सुलेमान सैट की आज यह हिम्मत पड़ी, उन्हें आज यह हौसला हुआ कि वह अपना मसूबा रिलीज़ करते वक्त यह कहें कि हम सेक्युलर हैं, हम मोहतरिम हैं इसलिए कि हम ने कांग्रेस के साथ समझौता किया है । मुझे उन की सियासत से इत्तफाक नहीं है लेकिन आई थिंक ही हैज़ ए प्वाइंट । उन तमाम ताकतों को मैं चैलेंज करता हुं, उन पर इल्ज़ाम लगाता हूं कि उन्होंने इस किस्म की जमात को यहां सहायता दी, उस के साथ नाजायज समझौता कर के मुस्लिम कम्युनलिज्म कोरेस्पेक्टेबिलिटी बख्शी । नतीजा यह है कि उन लोगों ने यू० पी० में वह वह तकरीरें कीं, वह वह जहरीली तकरीरें कीं कि मुझे हैरत नहीं है अगर इंतखाबात का यह हंगामा खत्म होने के बाद यू० पी० में फिरकादाराना तनाव पहले से ज्यादा बढ़ जाए ।

मेरा कहने का मकसद यह है कि इक्तिसाखियात में आप ड्राउट का सहारा ले सकते हैं, आप यह सहारा ले सकते हैं कि सारी दुनिया में ग्लोबल परस्पेक्टिव एकोनामिक का बड़ा खराब है, मैं आप को शक का फायदा दे कर रिहा करूंगा, मैं आप को माफी दूंगा लेकिन आप मुझे यह बताइए कि मुस्लिम लीग और शिव सेना के साथ, कांग्रेस (ओ०) के साथ समझौता करने में कौन सी कयामत थी ? कौन सी मजबूरी थी ? यही थी न कि आप एक स्टेट में हुकूमत नहीं बना सकते ।

[श्री एस० ए० शमीम]

क्या कांग्रेस जिस के पेशवा गांधी जी रहे हैं, जिस के पेशवा मौलाना आजाद और जवाहर लाल नेहरू रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट में पावर में रहने के लिए उन कातिलों के साथ समझौता करें जिन्होंने कि मुल्क का बटवारा किया है, मुस्लिम लीगी लीडर हों या मेरे जनसंघ दोस्त ये दोनों इस मुल्क के बटवारे के जिम्मेदार हैं आप इन मे से एक को बुरा कहते हैं और दूसरे को गले से लगाते हैं, आप कातिलों के साथ समझौता करते हैं, जिन के हाथों से खून की बू आती है और अफसोस का मुकाम यह है कि आज यू० पी० में वही खून पीने वाले, यही खून बहाने वाले सब्ज परचम ले कर मुसलमानों को बहकाने के लिए जाते हैं कि हम तुम्हारी आवाज को पालियामेंट में उठाएंगें। मैं समझता हूं कि यह सिस्टम काबिले कबूल नही है जहां इस किस्म के जहर फैलाने वाले, पार्लियामेंट के मेम्बर बन कर, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करें और यह कहे हम इस मुल्क मे तुम्हारी आवाज उठाना चाहते है। म मुसलमान हूं। मै जानता हू कि अगर फिरकादाराना फसाद हो तो मुझसे मेरी आइडियोलाजी पूछे बगैर मेरा कत्ल हो सकता है। लेकिन यह जाती मामला है। सवाल यह है कि जो स्टेजों पर चढ़ कर हाथ में कुरान और सब्ज परचम ले कर मुसलमानों को तलकीन करते हैं कि हिन्दु तुम्हारा दुश्मन है, हिन्दु को वोट मत दो—मेरी जनसंघ से बहुत पुरानी लड़ाई है, है, ये बड़े मौजी लोग हैं, मौजी का मतलब है बड़े जालिम, लेकिन अगर इन मौजियो को सहायता मिली है, अगर इन को जस्टिफिकेशन मिली है तो वह प्रोवाइड की है श्री सुलेमान सैट ने, मुस्लिम लीग के नये कायदे आजम श्री सुलेमान सैट ने जिन्होंने मुसलमानों की लाशो का सौदा कर के यू० पी० मे चन्द इन्तखाबी सीटें जीतने के लिए मुसलमानों को कहा कि तुम सब्ज परचम को वोट दो। आज उर्दू का रोना रोने वाले सुलेमान सैट को मै चैलेंज करता हूं ......

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट: (कोजीकोड़) आप किस की तरजुमानी कर रहे हैं ....

श्री एस० ए० शमीम : मैं तरजुमानी कर रहा हू उन बेजबान मुसलमानों की जिन को आप ने सब्ज परचम दिखा कर यह बताया कि हम तुम्हारी निजात चाहने वाले हैं। आप यह भूल गए कि वही मुस्लिम लीग जिस ने पाकिस्तान बनाया .....

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : यह वह मुस्लिम लीग नही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हू। यह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ....

श्री एस० ए० शमीम : अगर यह वह मुस्लिम लीग नही है ....

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मै कह सकता हू कौन सी मुस्लिम लीग है। आप क्या जानते है? आप इस के बारे मे क्या कह सकते है? आप किस की नुमाइन्दगी करते है?

श्री एस० ए० शमीम : मै आप से यह कह रहा था कि श्री सुलेमान सैट के कहने से मै यह बात नही मानता ....

MR. CHAIRMAN : I request you, Mr. Sulaiman Sait, not to interrupt him. Your party member had a chance.

Please do not interrupt him now. Let us keep order in the House. You will get the chance and when your turn comes, you may say what you want to say. Till then, you don't interrupt him. Please keep the order in the House.

श्री एस० ए० शमीम : Shri Sulaiman had one month's chance to poision the entire atmosphere in U. P.

आज 5 मिनट की स्पीच मे वह पायजान दूर नहीं हो सकता है, लेकिन बात कहने की इजाजत होनी चाहिये और चूंकि आप यहा मौजूद है, इस लिये आप से पूछता हू— मैंने आप की तकरीरों को पढ़ा है। आप ने कहा है कि यहां मुसलमानों ने हिन्दुओं को सलीका सिखाया है। आप के बनातवाला

ने कानपुर में तकरीर करते हुए कहा—मिसिज़ गांधी इस लिये यहां जिन्दा हैं कि मुसलमान इस मुल्क में मौजूद हैं, वरना वह भी फीरोजगांधी के साथ सती हो गई होतीं। आप ने मुसलमानों के सैन्टीमेन्ट्स को उभारने की कोशिश की है, मुसलमानों का खून करने के लिये मैदान हमवार किया है। यू० पी० में इन्होंने जो कुछ कहा है वह किसी से छिपा नहीं है, आप चूंकि यहां आ गये, इस लिये मुझे कुछ बातें कहनी पड़ीं। आप मुसलमानों की लीडरी का दावा करते हैं, आप के स्पीकर्स कहते हैं कि मुसलमानों की तरफ़ से हम बोलेंगे, पूरी पार्लियामेन्ट में ढाई मेम्बर हो और सात करोड़ मुसलमानों की नुमाइन्दगी का दम भरते हो, याद रखो यू० पी० में तुम्हारी जमानतें जब्त हो जायेंगी।

आर० एस० एस० को मैं गवारा कर सकता हूं, इसलिये कर सकता हूं, हिन्दू जनसंघ की एक आइडियोलिजी है। वह इस मुल्क में हिन्दू राज्य कायम करना चाहते हैं, तुम किस का राज्य कायम करना चाहते हो, क्या चरण सिंह का राज्य कायम करना चाहते हो। अगर तुम जीत भी जाओ, यू० पी० में तुम्हारे सारे उम्मीदवार जीत जाय, लेकिन तुम को फिर भी अक्सरियत नहीं मिलेगी, जब तक तुम को दूसरों का ऐतमाद हासिल नहीं होगा, हम इस मुल्क में तब तक जिन्दा नहीं रह सकते, जब तक सैकुलरिज्म को सरन्डर न करें। जब तक हिन्दुओं का ऐतमाद हासिल न करें। आप कांग्रेस का साथ न दें, लेकिन मुल्क में और भी सैकुलर जमायतें हैं—जिन का साथ दे सकते हैं। मुसलमानों को कम्यूनल प्लेटफार्म पर जमा करना मुसलमानों के लिये खतरा पैदा करना है। मैं जज़बात की रौ में बह कर यह बात नहीं कह रहा हूं, इस लिये कह रहा हूं कि मैंने यू० पी० में बड़ा हौलनाक नज़्ज़ारा देखा है। 1946 में इस मुल्क का बटवारा करानेवाली जमायत के लीडरान ने मुसलमानों से कहा कि हिन्दुओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुरान की आयतों के साथ जलसे शुरु होते, सब्ज परचम लहराया जाता और कहा जाता कि पता नहीं यहां पर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कैसे कायम है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं—अक्सर मिसालें दी जाती हैं कि दुनिया के मुमालिकों में मंहगाई बढ़ी है, दुनिया के मुमालकों में करप्शन है—मिसाल इंग्लैंड की दी जाती है, अमरीका की दी जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस मिसालों को वहीं तक क्यों महदूद रखते हैं। मैंने कहा था—उन मुल्कों में कुछ पार्लिमानी-कदरें हैं, पार्लिमानी रवायतें हैं, जिन का वे पालन करते हैं। अभी हाल में ग्रेट ब्रिटेन में स्ट्राइक हुई थी, बड़ा माइनर ईशू था, यहां तो रोज ही स्ट्राइक होती हैं, लेकिन वहां सिर्फ उस ईशू के लिये वहां की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया और कहा कि इलैक्शन होंगे। लेकिन आप तो यहां पूरी गद्दी के मालिक हैं, उस को छोड़ना ही नहीं चाहते। गुजरात में ऐसी स्थिति पैदा हुई—वहां सरकार को कहा गया कि चले जाओ, मंहगाई के लिये हमारे सामने ब्रिटेन की मिसालें लाते हो, अमरीका की मिसालें देते हो, तो उनकी तरह की रवायतें क्यों कायम नहीं करते, ताकि लोगों में विश्वास हो जाय कि ये हुकमरान गद्दी पर काबिज होने के लिये कीन नहीं है। आप ने यह कहा है कि हम हर कीमत पर हकूमत नहीं छोडेंगे, अगर आज आप ने मुस्लिम लीग को गले लगाया है, एक सांप को गले लगाया है तो कल मालूम नहीं किस जानवर को गले लगायेंगे और मुझे खतरा है कि एक दिन इन मूजियों को भी गले लगाओगे। कुछ कदरों का पालन करो, खुदा के लिये, इन्साफ़ के लिये उन कदरों का पालन करो।

شری ایس- اے - شمیم (شری نگر) :

چیرمین صاحب - پارلیمینٹ میں میرا جو تجربہ رہا ہے اس کی بنا پر تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ پارلیمینٹ کا انسٹیٹیوشن پارلیمینٹری سسٹم اور

[شری ایس۔ اے۔ شمیم]

پارلیمینٹری طریقہ کار اس ملک میں رفتہ رفتہ ارریلیوینٹ بنتا جا رہا ھے۔ میرا یہ احساس راشٹرپتی کا ایڈریس سننے کے بعد اور زیادہ مضبوط ھو گیا۔ کل جب نئے دور کا مہاتما ڈاکٹر کرن سنگھ یہاں تقریر کر رہے تھے ماریلیٹی سپیرچولزم اور ویلیوز پر تو میرا یہ وشواس اور زیادہ مظبوط ھو گیا۔ کہ اس ملک کی جنتا سے پارلیمینٹ کا تعلق اس کا رشتہ کٹتا جا رہا ھے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ ایک ناٹک کرتے ھیں۔ سرکاری دل ایک بات کہتا ھے اور اپوزیشن اس کا ورودھ کرتی ھے۔ اور اپوزیشن کوئی بات کہتی ھے تو سرکار کو اس کو مخالفت کرنی چاھیئے۔ یہ ھمارا رول رہا ھے۔ اب لوگوں کا اعتقاد رفتہ رفتہ پارلیمینٹری سسٹم پر سے اٹھتا جا رہا ھے۔

یہاں پر اکثر یہ بات کہی گئی کہ گجرات میں جو کچھ ھوا یا اس وقت ملک میں اھنسا کا جو دور چل رہا ھے اس کا سبب یہ ھے کہ کچھ اینٹی شوشل ایلیمینٹ اس سچویشن کو ایکسپلائیٹ کر رہے ھیں۔

یہ جاننے کی بات ھے کہ کیوں ھزاروں کی تعداد میں لوگ قانون توڑ کر گولیاں کھانے کے لئے آتے ھیں۔ کرفیو توڑتے ھیں۔ فوج کا مقابلہ کرتے ھیں۔ اس کا کارن کیا ھے۔ یہ کوئی شوق کی بات نہیں ھے۔ تماشہ کرنے کی بات نہیں ھے۔ اور جب نوجوان ھمارے پارلیمینٹری سسٹم پر وشواش کھو کر اس کے بعد سینہ تان کر گولیاں کھانے کے لئے آمادہ ھو جائیں تو اس کو آپ اپوزیشن کا کارنامہ کہہ کر اپوزیشن کو کریڈٹ دے رہے ھیں۔ جس کام کا اھل اپوزیشن نہیں ھو آپ اس کو وہ تغمہ دے رہے ھیں۔ اگر واقعی اس ملک میں اپوزیشن آج اتنی سٹرونگ ھے کہ وہ گجرات میں ایک خاموش نہیں طوفانی انقلاب پیدا کر سکتی ھے۔ تو میں سمجھتا ھوں کہ پھر تو کانگریس کو یہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاھیئے۔ لیکن میں سمجھتا ھوں کہ ان میں کانگریسی بھی ھیں۔ بد قسمتی سے ان کا پارلیمینٹری انسٹیٹیوشن سے وشواش اٹھتا جا رہا ھے۔ اس میں دوش کس کا ھے۔ میں دوش صرف حکمران جماعت کو نہیں دینا چاھتا۔ میں اس بات کو کہنا چاھتا ھوں کہ جمہوریت کی قدروں کو پامال کرنے کے لئے پارلیمینٹری انسٹیٹیوشن پر وشواش ختم کرنے کے لئے اگر سرکاری جماعت ملزم ھے تو اپوزیشن بھی برابر ملزم ھے۔ ھم سب نے مل کر اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کا ستیاناش کرکے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ھے کہ آج سب سے زیادہ کنٹیمپٹ کا مرکز جو ھے وہ لیجسلیٹر ھے۔ پارلیمینٹرین ھے۔ چاھے وہ اپوزیشن کو بیلانگ کرتا ھے چاھے سرکاری جماعت کو۔ لیکن یہ کہنے کے بعد یہ بات

لیکن ایک وشواش تھا کہ گاندھی جی ایک آئیڈیل ھیں - جواھر لال جی ایک آئیڈیل ھیں - یہ کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کر سکتے یا کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے - جس سے جنتا کا وشواش ختم ھو جائے - لیکن اب سب سے بڑی بات جو ھو رھی ھے وہ یہ ھے کہ آپ لوگ اس ملک پر حکومت کر رھے ھیں وہ ۲۷ برسوں سے کر رھے ھیں - اس بدقسمت ملک کے ایوان پر - آپ ھمارے آئیڈیل نہیں ھیں - آپ کی کوتاھیوں کا نتیجہ کیا ھو رھا ھے؟ یہ الگ ایک بات ھے - اس وقت ملک میں اکنومک سفیئر میں بڑی گھمبیر سچویشن ھے یہ گھبرانے کی ضرور بات ھے - ملک میں اس وقت بیچینی ھے - یہ گھبرانے کی ضرور بات ھے - اس کے لئے پریشان ھونے کی ضرور بات ھے - لیکن سب سے زیادہ خطرہ جو اس وقت ھے سب سے بڑی مشکل جو اس وقت ھے وہ یہ ھے کہ ان حالات کو پیدا کرنے میں حکمران جماعت اور اپوزیشن ملکر ایک ماحول تیار کر رھی ھیں جس میں سب سے زیادہ فائیدہ اس ملک کے فرقہ دارانہ کمیونل ایلیمینٹس کو ھو رھا ھے -

مجھے افسوس ھے کہ میرے دوست مسلم لیگ کے محمد کویا یا نئے مسلم لیگ کے قائید اعظم شری سلیمان سیٹ یہاں نہیں ھیں - وہ یہاں ھوتے تو میں ذرا کھل کر بات کرتا - کہ بہت ضروری ھو جاتی ھے کہ اس میں سب سے زیادہ دوش کس کا ھے - سب سے زیادہ گالی کس کو ملنی چاھئیے - سب سے زیادہ سزا کس کو ملنی چاھئیے - ۲۷ سال اس ملک کی حکومت آپ کے ھاتھ میں رھی - آج اگر گجرات کے لوگوں کا لاوا اتنے زور سے ابلنے لگا - آج اگر مہاراشٹر میں بیچینی ھے تو سوال ھے کہ اس کا دوش کس کو جائے گا - آپ کہتے ھیں کہ بھاکڑا ھم نے بنایا - بوکارو ھم نے بنایا اس ملک میں ھم نے اتنی ترقی کی اس کے لئے آپ داد چاھتے ھیں - تالی چاھتے ھیں - لیکن ھر بات کے لئے تالی مل سکتی ھے تو اور جو کچھ ملک میں ھو رھا ھے اھنسا ھو رھی ھے - بھکمری ھے - اس کے لئے آپ کو گالی بھی ضرور ملنی چاھئے - آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میٹھا میٹھا ھڈپ - اس کے لئے تالی بجاؤ - لیکن اگر کوئی برا کام ھو رھا ھے تو وہ اپوزیشن کے سر پر تھوپیں -

سب سے بڑی بات ویلیوز کی ھے - سب سے زیادہ باتیں اس معاملے میں ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہیں - ویلیوز کی باتیں ھیں - گاندھی جی اس ملک میں تھے - جواھر لال نہرو اس ملک میں تھے - اس ملک میں کرپشن اس وقت بھی تھی - بھوک اس وقت بھی تھی - اس ملک میں بیکاری اس وقت بھی تھی -

[شری ایس - اے - شمیم

حکمران جماعت کی ناکامیوں سے فائیدہ اٹھا کر اس ملک میں ایک بار پھر ۱۹۴۵ اور ۱۹۴۷ کا سا ایٹموسفئیر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد کویا صاحب نے کل کہا کہ وہ مسلم کمیونیٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں - اور صرف وہ یہ حق رکھتے ہیں - کہ مسلمانوں کی باتوں کو کہیں - اگر ہندوستانی مسلمانوں نے محمد کویا کو یہ حق دیا ہوتا یا شری سلیمان سیٹ کو یہ حق دیا ہوتا تو آج مسلمانوں کا اس ملک میں وجود بھی نہیں ہوتا - مسلمانوں کا سات کروڑ کی تعداد میں یہاں رہنا اس بات کی ضمانت ہے کہ انہوں نے وشواش کیا ہے اس ملک کی اکثریت جماعت پر - اس ملک کے ہندؤں پر - ان سیکولر عناصر پر - جنہوں نے ۱۹۴۷ کے خونی ڈرامے میں بھی کہا کہ جاہے پاکستان اپنا ملک اسلامی آدھار پر بنائے - لیکن ہندوستان سیکولر ارادے پر قائیم رہیگا - اور ہندوستان کو سیکولر آئین دیا - اس وقت مسلم لیگ کے یہ قائید اعظم جو آج سبز پرچم لیکر مراداباد - حیدراباد اور یو-پی میں پھر رہے ہیں اس وقت ان کا کوئی وجود نہیں تھا - مجھے یو- پی - کے حالی انتخابات میں کچھ علاقوں کا دورا کرنے کا موقعہ ملا - حیرت ہے کہ اس ایوان میں بہت سے لوگوں نے برائی کی سرکار کی کہ انہوں نے شو سینا کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے - لیکن میں الزام لگاتا ہوں میرا چارج ہے اس سرکار پر کہ اس ملک میں اس حکومت نے مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کرکے کیرل میں مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کرکے اس ملک کی ایکتا کو سیکولر فورسز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے - یہ وجہ ہے کہ شری سلیمان سیٹ کی آج یہ ہمت پڑی انہیں آج یہ حوصلہ ہوا کہ وہ اپنا منسوبہ ریلیز کرنے وقت یہ کہیں کہ ہم سیکولر ہیں - ہم محترم ہیں اس لئے کہ ہم نے کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے - مجھے ان کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے - لیکن آئی بھنک ہی ہیز اے پائینٹ - ان تمام طاقتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں - ان پر الزام لگاتا ہوں - کہ انہوں نے اس قسم کی جماعت کو مہان سہارا دیا دی - اس کے ساتھ ناجائیز سمجھوتا کرکے مسلم کمیونیلزم کو ریسپیکٹیبلیٹی بخشی - نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یو- پی - میں وہ وہ تقریریں کیں - وہ وہ زھریلی تقریریں کیں کہ مجھے حیرت نہیں ہے اگر انتخابات کا یہ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد یو - پی - میں فرقہ دارانہ تناؤ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے -

میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکنیساخیات میں آپ ڈراوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں - آپ یہ سہارا لے سکتے ہیں - کہ ساری دنیا میں گلوبل پراسپیکٹیو اکنومک کا بڑا خراب ہے -

چاھتے ھیں - میں مسلمان ھوں - میں جاننا چاھتا ھوں کہ اگر فرقہ دارانہ فساد ھوں تو مجھ سے میری آئیڈیولوجی پوچھے بغیر میرا قتل ھو سکتا ھے - لیکن یہ ذاتی معاملا ھے - سوال یہ ھے کہ جو سٹیجوں پر چڑھ کر ھاتھ میں قران اور سبز پرچم لے کر مسلمانوں کو تلقین کرتے ھیں کہ ھندو تمھارا دشمن ھے ھندو کو ووٹ مت دو - میری جن سنگھ سے بہت پرانی لڑائی ھے - یہ بڑے موذی لوگ ھیں - موذی کا مطلب ھے بڑے ظالم - لیکن اگر ان موذیوں کو سہائتا ملی ھے اور ان کو جسٹیفیکیشن ملی ھے تو وہ پرووائیڈ کی ھے شری سلیمان سیٹ نے - مسلم لیگ کے نئے قائید اعظم شری سلیمان سیٹ نے جنھوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا سودا کرکے یو - پی - میں چند انتخابی سیٹیں جیتنے کے لئے مسلمانوں کو کہا کہ تم سبز پرچم کو ووٹ دو - آج اردو کا رونا رونے والے سلیمان سیٹ کو میں چیلنج کرتا ھوں......

شری ابراھم سلیمان سیٹ : آپ کس کی ترجمانی کر رھے ھیں -

شری ایس اے شمیم : میں ترجمانی کر رھا ھوں ان بے زبان مسلمانوں کی جن کو آپ نے سبز پرچم دکھا کر یہ بتلایا کہ ھم تمھاری نجات چاھنے والے ھیں - آپ یہ بھول گئے کہ وھی مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا -............

میں آپ کو شک کا فائیدہ دے کر رھا کرو نگا - میں آپ کو معافی دونگا - لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ اور شو سینا کے ساتھ - کانگریس (O) کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں کونسی قیامت تھی - کون سی مجبوری تھی - یہی تھی تا کہ آپ ایک سٹیٹ میں حکومت نہیں بنا سکتے - کیا کانگریس جس کے پیشوا گاندھی جی رھے ھیں - جس کے پیشوا مولانا آزاد اور جواھر لال نہرو رھے ھیں - صرف ایک سٹیٹ میں پاور میں رھنے کے لئے ان قاتلوں کے ساتھ سمجھوتا کرے جنھوں نے ملک کا بٹوارا کیا ھے - مسلم لیگی لیڈر ھیں یا میرے جن سنگھی دوست - یہ دونوں اس ملک کے بٹوارے کے ذمے دار ھیں - آپ ان میں سے ایک کو برا کہتے ھیں - اور دوسرے کو گلے سے لگاتے ھیں - آپ قاتلوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ھیں - جن کے ھاتھوں سے خون کی بو آتی ھے - اور افسوس کا مقام یہ ھے کہ آج یو - پی - میں خون پینے والے یہی خون بہانے والے سبز پرچم لے کر مسلمانوں کو بہکانے کے لئے جاتے ھیں - کہ ھم تمھاری آواز کو پارلیمینٹ میں اٹھاینگے - میں سمجھتا ھوں کہ یہ سسٹم قابل قبول نہیں ھے جہاں اس قسم کے زھر پھیلانے والے - پارلیمینٹ کے ممبر بن کر پارلیمینٹ کے فورم کو استعمال کریں اور یہ کہیں کہ ھم اس ملک میں تمھاری آواز اٹھانا

شری ابراهیم سیٹ سلیمان : یه وه مسلم لیگ نہیں ہے - میں ذمےداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں - یه گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے -

شری ایس اے شمیم : اگر یه وه مسلم لیگ نہیں ہے ....

شری ابراهیم سیٹ سلیمان : میں کہہ سکتا ہوں کونسی مسلم لیگ ہے - آپ کیا جانتے ہیں - آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں - آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں -

شری ایس - اے - شمیم : میں آپ سے یه کہہ رہا تھا که شری سلیمان سیٹ کے کہنے سے میں یه بات نہیں مانتا -

MR. CHAIRMAN : I request you, Mr. Sulaiman Sait, not to interrupt him. Your party member had a chance. Please do not interrupt him now. Let us keep order in the House. You will get the chance and when your turn comes, you may say what you want to say. Till than, you don't interrupt him. Please keep the order in the House.

SHRI S. A. SHAMIM : Shri Sulaiman Sait had one month's chance to poison the entire atmosphere in U.P.

اس پانچ منٹ کی سپیچ میں وه بوائنٹ دور نہیں ہو سکتا ہے لیکن بات کہنے کی اجازت ہونی چاہئے - اور چونکه آپ یہاں موجود ہیں - اس لئے میں آپ سے پوچھنا ہوں - میں نے آپ کی تقریروں کو پڑھا ہے - آپ نے کہا ہے که یہاں مسلمانوں نے ہندوؤں کو سبق سکھلایا ہے - آپ کے بنات والا نے کانپور میں تقریر کرتے ہوئے کہا - مسز اندرا گاندھی اس لئے یہاں موجود ہیں که مسلمان اس ملک میں موجود ہیں - ورنه وه بھی فیروز گاندھی کے ساتھ ستی ہو گئی ہوتیں - آپ نے مسلمانوں کے سینٹیمینٹس کو ابھارنے کی کوشش کی ہے - مسلمانوں کا خون کرنے کے لئے میدان ہموار کیا ہے - یو- پی - میں انہوں نے کچھ کہا ہے وه کسی سے چھپا نہیں ہے - آپ چونکه یہاں آ گئے اس لئے مجھے کچھ باتیں کرنی پڑیں - آپ مسلمانوں کی لیڈری کا دعوه کرتے ہیں - آپ کے سپیکر کہتے ہیں که مسلمانوں کی طرف سے ہم بولینگے - پوری پارلیمنٹ میں ڈھائی ممبر ہو- اور سات کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کا دم بھرتے ہوں - یاد رکھو یو- پی - میں تمہاری ضمانتیں ضبط ہو جائینگیں -

آر- ایس - ایس - کو میں گوارا کر سکتا ہوں - اس لئے کر سکتا ہوں ہندو جن سنگھ کی ایک آئیڈیولوجی ہے - وه اس ملک میں ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں - تم کس کا راج چاہتے ہو- کیا چرن سنگھ کا راج قائم کرنا چاہتے ہو- اگر تم جیت بھی جاؤ یو- پی - میں تمہارے اور امیدوار جیت جائیں - لیکن تم کو پھر بھی اکثریت نہیں ملے گی - جب تک تم کو دوسروں کا اعتماد حاصل نہیں ہم اس ملک میں تب تک زندہ نہیں رہ سکتے - جب تک که سیکولرزم کو سرنڈر نه کر دیں - جب تک ہندوؤں کا اعتماد حاصل نه کریں - آپ کانگریس کا ساتھ نه دیں -

لیکن ملک میں اور بھی سیکولر جماعتیں ہیں - جن کا ساتھ دے سکتے ہیں - مسلمانوں کو کمیونل پلیٹ فارم پر جمع کرنا مسلمانوں کے لئے خطرہ پیدا کرنا ہے - میں جزبات کی رو میں بہہ کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں - اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یو-پی -میں بڑا ہولناک نظارہ دیکھا ہے - ۱۹۴۶ میں اس ملک کا بٹوارا کروانے والی جماعت کے لیڈران نے مسلمانوں سے کہا کہ ہندؤں پر وشواش نہیں کیا کیا جا سکتا - قران کی ائتوں کے ساتھ جلسے شروع ہوتے - سبز پرچم لہرایا جاتا اور کہا جاتا کہ یہاں نہیں یہاں پر پارلیمینٹری سسٹم کیسے قائیم ہے ..

میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں - اکثر مثالیں دی جاتیں ہیں کہ دنیا کے ممالکوں میں مہنگائی بڑھی ہے - دنیا کے ممالکوں میں ٹریشن ہے - مثال انگلینڈ کی دی جاتی ہے اور امریکہ کی دی جاتی ہے - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مثالوں کو یہاں تک کیوں محدود رکھا گیا ہے - میں نے کہا تھا کہ ان ممالکوں میں کچھ پارلیمانی قدریں ہیں - پارلیمانی روائتیں ہیں - جن کا وہ پالن کرتے ہیں - ابھی حال میں گریٹ بریٹن میں سٹرائیک ہوئی تھی - بڑا مائینر اشو تھا - یہاں تو روز ہی سٹرائیکیں ہوتی ہیں - لیکن وہاں صرف اس ایشئو کے لئے وطن کی گورنمینٹ نے ریزائین کر دیا - اور کہا کہ الیکشن ہوں گے - لیکن آپ تو یہاں پوری گدی کے مالک ہیں - اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے - گجرات میں ایسی ستیتھی پیدا ہوئی ہے - وہاں سرکار کو کہا گیا کہ جاو مہنگائی کے لئے ہمارے لئے بریٹین کی مثالیں لاتے ہو - امریکہ کی مثالیں دیتے ہو - تو ان کی طرح کی روائیتیں کیوں قائیم نہیں کرتے - تاکہ لوگوں میں وشواش ہو جائے کہ یہ حکمران گدی پر قابض ہونے کے لئے کین نہیں ہیں - آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر قیمت پر حکومت نہیں چھوڑینگے - اگر آج آپ نے مسلم لیگ کو گلے لگایا ہے ایک سانپ کو گلے لگایا ہے تو کل معلوم نہیں - کس جانور کو گلے لگائینگے - اور مجھے خطرہ ہے کہ ایک دن ان موذیوں کو بھی گلے لگائیں گے - کچھ قدروں کا پالن کرو خدا کے لئے - انصاف کے لئے ان قدروں کا پالن کرو . . . . . شکریہ -]

SHRI S. A. KADER (Bombay-Central South) : I was tempted to participate in this discussion after hearing my revered leader Shri Morarji Desai. He dealt with the various aspects of the present situation in the country and also made some suggestions. As to how far they will be practicable and useful, he himself knows. But he made one big or tall claim that during his time, when they were in power, the food situation in this country was all right. He quoted the figure of 72 million tonnes food production in 1965 and 74 million tonnes in 1966, and during 1971 and 1972, the total for the two years came to about 195 million tonnes. But at the same time, he should have drawn attention to what the popu'ation of the country was at that time. According to the census figure of 1961, the population was 43.90 crores.

while according to the 1971 figure, the population is 54.80 crores, an increase of about 11 crores. The food production has not increased to the extent required, inkeeping with the total increase in population. I say that this is one of the reasons for the present stage of maldistribution. It may be that other causes are there. But I do concede that it is not only that the food production has not kept pace with the increase in population, but whatever food has been produced has not been equitably or properly distributed.

When the food policies are being evolved, we are not taking India as a whole but we are dealing with it compartmentally.

We cannot import or export from one State to another. Now, the restrictions have gone down even to the zila and taluka levels. What is needed is a very dynamic and bold food policy so that we shall not have a continuation of the present phenomenon when cheaper grains are available at one place, say, rise at Rs. 1.20 per k.g. at Moga, while at another place, the price is Rs. 4 or 5. Either the food control should be properly and equitably done or otherwise there sould be some method to ensure that the people get the cereals which they require at reasonable prices

Today, only about 3 kg or 4 kg are supplied. What is required is about 8 to 10 kg. and at least 8 kg. But even this minimum is not being distributed to say in many places.

Then, Shri Morarji Desai referred to corruption. I would like to ask him since when he has realised that there is corruption.

SHRI S. A. SHAMIM : 1971.

SHRI S. A. KADER : Corruption was there from the beginning when we took over from the British Government. In fact, it was there even before that, but we took it longside with that. It is said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. That process had started not after 1971 but it had started from 1947 onwards from that time onwards, values have begun to change. Power was for *Seva,* but it became self-*Seva* and not *Seva* of the *Janata.* This is what has happened, and I think the leadership from that time onwards up till now is also responsible for having changed these values and bringing us to this position today. Shri Kamaraj Nadar had once said, 'I take my responsibility for what has happened from 1946 till now.' That is the correct way. I would have expected Shri Morarji Desai to take his share of the responsibility for bringing about corruption.

Why there is corruption? One important cause is the present election system. It is not a party matter, it is a national question. As long as the present election system is there, every party will have to depend on corruption

SHRI N.K.P SALVE (Betul): What is your alternative ?

SHRI S A. KADER : We will have to have some rethinking about it It is not easy to say 'this is the alternative' This requires complete rethinking We have had experience of this for 25 years We should now see that elections are so managed that the parties have not to depend on black money, whether it is the Congress party or any other party One of the contributory factors for the existence of a parallel economy, a white market and a black market, is the election system which keeps the black market going Therefore, very radical steps should be taken to mitigate this kind of corruption.

I would make this appeal It is a question for all parties in this country They should sit together and evolve a method and then come and say that this is the way our elections will be run hereafter

The second point is this It has been so planned that every year we are having elections, either in a zila parishad or in a State or to Parliament Instead of devoting all our energies to the constructive tasks of the State and the country, every time we fight amongst ourselves in elections. All said and done, election creates bad blood every time. Therefore, there should be the minimum of election. Of course, if you want to maintain the democratic system, there must be elections, but at what time and what type of elections, these are things which require consideration.

I would now refer to my friend Shri Koya's speech. Shri Koya is not here, but Shri Suleiman Sait is here. Shri Koya made, according to him, a very good speech. He said, "I am talking about some important matters pertaining to a certain community". Now it is my stand and I hope it is the stand of the House, of all of us, that in this House no member can say who represents which community. There is not a single constituency in this country where you can say that only one community or people belonging to one religion are the voters and nobody else. There must be non-Muslims in Shri Koya's constituency also; having got votes from non-Muslims also, it does not lie in his mouth to say that he represents only a particular community. Take my constituency for example. The Muslim voters there are hardly 96,000 out of a total of 7 lakh voters. If I say that I am a Muslim and so I speak on behalf of Muslims, it is irrelevant and illogical.

SHRI N. K. P. SALVE: And untrue.

SHRI S. A. KADER: We speak here on behalf of the people, on behalf of our constituencies as a whole. We cannot isolate a certain chunk of the population and say that we speak on their behalf. This is a fundamental thing that was to be understood. The sooner we understand it the better for all of us.

Then he spoke about the Urdu language. He said it should be recognised and made the second language wherever it is spoken. To that extent, I agree with him that wherever it is predominently spoken, it should be done. He cannot take the name of a community to urge this. Urdu is not the language of Muslims as such. I corrected him then. He also agreed with me. My friend, Shri Sulaiman Sait will also agree.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): Definitely; it is an Indian language.

SHRI S. A. KADER: Then why are you putting it that way? Let those people whose mother tongue is Urdu and want it to be safeguarded press for it. There are thousands of non-Muslims whose mother tongue is Urdu. Today one who is carrying the banner of Urdu in the Rajya Sabha is a non-Muslim, our friend Shri A. N. Mulla. These are the people who are affected. But Urdu is not the language of only Muslims. It had been made a plank in the Muslim League agitation to strengthen the two-nation theory.

At that time, we were told that the Muslims and the Hindus were two separate nations. And what is the reason? One reason is that they are different religions; secondly, the language of Muslims is Urdu. These were the reasons which were adduced to the two-nation theory. My friend Shri Sulaiman Sait will bear me out. Are you still holding that view? If you are not holding that view, then why is it that you are again putting on behalf of the Muslim League the same slogan which was put before 1947?

*

Sir, it seems the Muslim League claims that they are a different organisation. But what I feel is that they are the same old wine in a new bottle.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: They have no parentage.

SHRI S. A. KADER: It is not in the interests of the Muslims or Urdu. If anyone has done harm to this beautiful Urdu language, no other party than the Muslim League has done it. That is one reason why today Urdue is suffering. (*Interruptions*) Therefore, I request my friend Shri Sulaiman Sait that it is high time you spoke less on Urdu and let those people speak about Urdu who are affected by it and let them do it. Do not please bring them on the communal platform which you represent. That is my humble submission, if you are really a lover of Urdu. If you are not really a lover of Urdu, then, you are only a politician, of course, any means or anything may be followed by you.

The second thing that I want to point out to Shri Sulaiman Sait is this. It is the way in which appeals were made in the recent Uttar Pradesh elections and in other elections. I am not only telling him. I am telling also those persons including even the political parties.

[Shri S. A. Kader]

who try to mobilise or polarise the Muslims votes for the sake of the party or for the sake of the individual or for the sake of their own gains. They are leading the Muslim masses into another five years of perpetual fear. I tell you this, because there are four or five parties in election. If you go and tell the Muslims, "You Muslims should vote only to their party because the Muslims will be protected by them," the other four parties will become enemies. That is why there are so many communal riots after the elections. All the communal riots that have taken place in Independent India have no religious basis. It is all on a political basis. Therefore, I would urge that if the interests of the Muslims were at your heart and not politics, if the interest of the common Muslims is at your heart, the only way is to see that the Muslims of India are brought into the mainstream of Indian political life and culture and to see that they progress as India progresses.

I would be one with you to fight injustice on the basis of community or communalism. But I shall not and will not appeal to my Muslim brethren to vote for me or vote for my party just because they are Muslims. If they are Indians, if they belong to this country and are born and bred in this country, if they think that they are Indians, they should be made to think that they are Indians and to take a broad perspective of the national character, and they should be brought into the mainstream. Then alone Muslim community and the Muslim usages will be safe. Otherwise, you are exposing all the good values of Islam for your political purpose and a day will come when these things will be exploited by the other parties.

I will not call names. You will be doing a big dis-service to the Muslim community because of your political games. You will have to make a choice, whether you want to serve the Muslims: then bring them into the mainstream; if you want to serve yourself, then you can go along as you are doing.

श्री जांबुवंत धोटे (नागपुर) : सभापति महोदय, आज हमारा राष्ट्र संक्रमण काल के उत्तरार्ध से गुज़र रहा है। ऐसी अवस्था में आप सुबह कोई भी अखबार उठाकर देखें तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि कहीं न कहीं गोलीबार हुआ, कहीं न कहीं लाठी-चार्ज हुआ, कहीं न कहीं अश्रु गैस के शेल्स बरसाये गए, कहीं पर हड़ताल हुई, कहीं पर बन्द का कार्यक्रम रहा, कहीं पर घेराव हुआ और कहीं पर हजारों लोग जेल में ठूंस दिये गए या गोलियों से भून दिये गये। इसका मतलब साफ है कि सरकार विरोधी जनता का संग्राम हमारे देश में आज शुरू हो गया है। शासनकर्त्ता, शासन-व्यवस्था तथा शासन विरुद्ध जनता का टकराव हमारे देश में शुरू हुआ है और लोगों के ऊपर ऐसी अवस्था में जब लोग रोज़ी-रोटी के लिये, अपने सवालात राज्य-कर्त्ताओं के सामने पेश करने के लिये आगे आते हैं, रोज़ी-रोटी माँगते हैं उस वक्त शासनकर्त्ता उनको गोलियों से भून देते हैं, डंडों और गोलियों के बलबूते पर इस देश की जनता के ऊपर शासनकर्त्ता आज हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन मैं जाहिराना तौर पर बतला देना चाहता हूं कि दुनिया में आज तक किसी ने भी डंडे और गोलियों के भरोसे पर जनता पर हुकूमत नहीं की है। आज सरकार डंडा, गोली और ताकत के भरोसे पर पुलिस के ज़रिये हुकूमत करना चाहती है। इसी में जम्हूरियत की हत्या है। आज हमारा प्रजा-तंत्र खतरे में आया है। ऐसी बातें सारी ओर से कही जा रही हैं। पार्टी इन पावर की तरफ़ से यही दलीलें पेश की जाती हैं और विरोधी दलों की तरफ से भी यही दलीलें बारबार पेश की जाती हैं। ऐसी अवस्था में आज का जो पीरियड है, चरण है यह क्रान्ति पर्व है। सही माने में इन्कलाब और क्रान्ति का पर्व है और इसमें से हम आगे गुज़र रहे हैं। लेकिन इन्कलाब को, क्रान्ति को एक नेतृत्व चाहिये, और क्रान्ति एक शास्त्र, एक साइन्स होती है, बदकिस्मती से हमारे देश में जो इन्कलाब है, क्रान्ति है उस का नेतृत्व करने के लिये नेतृत्व

न तो पार्टी इन पावर के पास है और न अपोज़ीशन के पास है। इसलिये क्या हो रहा है ? एक तो रिवोल्यूशन की साइंस है उसको हमने स्टडी नहीं किया और क्रान्ति को जो नेतृत्व चाहिये वह नेतृत्व आज हमारे देश में दोनों ओर नहीं है, ऐसी अवस्था में जो क्रान्ति का पर्व है, इन्कलाब का जो चरण है इसकी जगह अनार्की, अराजकता ले रही है। और क्रान्ति की जगह जब अनार्की लेती है उस वक्त क्या होता है वह आप गुजरात में देख रहे हैं। बम्बई में गोलियां चलायी जाती हैं, विदर्भ में पुलिस की ओर से लोगों को भून दिया जाता है और डंडे के बल पर लोगों पर शासन किया जाता है। गुजरात हो, विदर्भ हो, हम कहना चाहते हैं कि इसी ढंग से यदि राज्यकर्त्ता अपनी राजनीति चलाते रहे तो गुजरात के रास्ते पर सारा देश जायेगा। आज गुजरात उस रास्ते पर जा रहा है कल को बम्बई जायेगा, विदर्भ जायेगा और उत्तर प्रदेश भी जा रहा है तथा बंगाल भी जायेगा। हम उन्माद में हैं सत्ता के। क्या हो रहा है क्या नहीं यह सोचते ही नहीं हैं। केवल हुकूमत करना चाहते हैं। विधान सभा, लोक सभा, जिला परिषद् आदि में चुन कर आना चाहते हैं। लेकिन वह भी चुनाव का नतीजा ज़ाहिर है। पांडिचेरी में क्या हुआ ? हमने देखा पार्टी इन पावर और संगठन कांग्रेस जो जुदा हुए बंगलौर में, फिर पांडेचेरी में मिले। तो क्या नतीजा हुआ वह भी हम ने देखा। मणिपुर में भी देखा और उत्तर प्रदेश में क्या होगा वह भी देखेंगे। और लोक सभा के बाई इलेक्शन में जो कल फ़ैसला आया उसमें भी देखा कि क्या नतीजा निकला। राज्यकर्त्ताओं के ऊपर लोक अपना अविश्वास क्यों प्रकट कर रहे हैं ? बम्बई में वही देखा और नागपुर में भी यही देखा। जब जनता ज़ाहिराना तौर पर मैदान में आ कर अपना अविश्वास शासन-कर्त्ताओं पर प्रकट कर रही है उस वक्त गोलियों से शासन चलाने की कोशिश करना स्वयं प्रजातन्त्र को पांव के नीचे कुचलने की कोशिश करना है। यह राज्यकर्त्ताओं को ख्याल में रखना चाहिये। यदि रिवौल्यूशन को लीडरशिप हासिल नहीं हो तो वह अनार्की में बदल जायेगा। फ्रांस का रिवौल्यूशन हमने देखा उसमें प्रभावी नेतृत्व नहीं था जिसका नतीजा हुआ कि फ्रांस की राज्य क्रान्ति कुछ दिनों के बाद अराजकता में परिवर्तित हो गई। और चीन में जब च्यांगकाईशेक थे उस जमाने में जो अराजकता फैली थी उसको माउत्सेतुंग जैसा नेता मिला जिसने वहां के जन-असंतोष को सही मोड़ दिया, नेतृत्व दिया और अराजकता को क्रान्ति में परिवर्तित किया।

आज रेडियो, अखबारों में बहुत सारी खबरें पार्टी इन पावर की ओर से आती हैं जिनसे हमको यही दिखाई देता है कि सारी तरफ़ असंतोष है और उस असंतोष को बटोरने की कोशिश कुछ लोग करना चाहते हैं। राज्यकर्त्ता कहते हैं कि अपोज़ीशन के लोग इसका फ़ायदा उठा कर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं राज्यकर्त्ताओं को बताना चाहता हूं कि हम अपोज़ीशन के लोग क्या पार्टी इन पावर की गलत नीतियों की तारीफ़ करेंगे ? हमारा हक है लोगों का असंतोष बटोरना और उसको बटोर कर पार्टी इन पावर का पांव सही रास्ते पर लाना। यह आरोप करना कि विरोधी दलों के लोग असंतोष का फायदा उठाते हैं, निराधार है। आखिर असंतोष आप ही की तो देन है। असंतोष आप की नीतियों ने निर्माण किया है चाहे वह नीतियां आर्थिक हों, सामाजिक हों, या राजनीतिक हों और उस असंतोष को हम संगठित नहीं करेंगे और आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? ऐसी स्थिति में जब प्रजातन्त्र ही खतरे में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो राज्यकर्त्ताओं को अन्तर्मुख होकर देखना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हम इस देश में क्या लाना चाहते हैं ? माननीय साले भाई अब्दुल कादर, जो हमारे साथ विधान सभा में रहे, जब उन्होंने कहा यह जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम इसमें चुनाव का जो ढंग है इस ढंग से कुछ नहीं होगा, उसी वक्त हमारे मित्र माननीय सालवे

[श्री जाम्बुवंत धोटे]

ने पूछा कि आल्टरनेटिव क्या है ? आज हमारे देश में प्रजातन्त्र का आल्टरनेटिव क्या है यही खोज हर जगह हो रही है। आज प्रजातन्त्र बहुत बुरे ढंग से नाकामयाब साबित हुआ है। तो ऐसे समय प्रजातन्त्र का आल्टरनेटिव क्या है, उसकी जगह दूसरी आइडियालाजी क्या है, इसी की खोज में हैं।

गुजरात में जो हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात का आन्दोलन कोई नेताओं या दलों ने नहीं शुरू किया है। बल्कि जनता ने शुरू किया है। आन्दोलन हुआ तो चलती हुई ट्रेन में कुछ दल बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की जनता ऊब रही है, और जनता को सम्हालने के लिये, उनके सवालात को हल करने के लिये इन बुनियादी तौर पर कुछ नहीं सोच रहे हैं, सोचना नहीं चाहते। बल्कि उल्टे राष्ट्रपति शासन लगा कर डंडा चला कर या विधान सभा भंग कर के वहां के सवाल हल नहीं कर सकते। तो जो रोजी रोटी का सवाल है उसके बारे में हमारी क्या नीति है ? हम सारे लोगों को खुश करना चाहते हैं, पूंजीपतियों को एक तरफ खुश करना चाहते हैं, सामन्तवादियों को एक तरफ खुश करना चाहते हैं, और मेहनतकश लोगों को, गरीबों को खुश करना चाहते हैं, और उस नतीजे में हम आखिर में किसी को भी खुश नहीं कर सकते। केवल पालियामेंट, असेम्बली, जिला परिषद् में चुनकर आने की सारी हमारी चेष्टा हो रही है।

[श्री जाबुवंत धोटे]

17 hrs.

हम संक्रमणकाल में से हो कर गुजर रहे हैं। इस संक्रमणकाल में क्रान्ति का वाहक नौजवान ही बन सकता है। जनता और सरकार में जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें जनता का वाहक, क्रान्ति का वाहक नौजवान ही तो है। नौजवान आज आलटरनेटिव खोज रहा है। उस दृष्टि से मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि पालियामेंट इसी ढंग से चली जैसे चल रही है, पालिमेंट में यही बचपने ढंग से कुछ लोग पेश आते रहे, बोलते वक्त कुछ भी बेढंग से कहते रहे तो शासनकर्ताओं पर से लोगों का विश्वास तो उठ ही गया है पालिमेंट पर से भी उठ जाएगा। राज्यकर्त्ता गोली चला रहे हैं, उसका सहारा ले रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि जो बोओगे वही काटोगे। गेहूं बोओगे गेहूं निकलेगा। गोली चलाओगे, गोली निकलेगी; लाठियां चलाओगे, लाठियां निकलेंगी। राज्यकर्त्ता पालिमेंटरी डेमोक्रेसी चलाने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन बन्दूक की गोली के सहारे वह नहीं चल सकती है। पुलिस और मिलिट्री के पास बन्दूक हो सकती है, लाठियां हो सकती हैं गुजरात में तथा दूसरे देश के हिस्सों में लेकिन लोगों के हाथ में लाठियां और गोलियां नहीं हो सकती हैं। शासनकर्त्ताओं को यह चीज समझ लेनी चाहिये। मूर्खों के नन्दन वन में आप बसर कर रहे हैं। राज्यकर्त्ताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस अवस्था में से हम गुजर रहे हैं, जो हालात हैं, अगर ये इसी तरह से चलते रहे और हालात इसी तरह से बनते चले गए, बिगड़ते चले गए तो भविष्य में पालिमेंट्री डेमोक्रेसी के बदले में तानाशाही, डिक्टेटरशिप की स्थापना अगर हुई तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं राज्यकर्त्ताओं पर होगी। यह मैं आपको आज बता देना चाहता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण किया है उसके लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री कादर और श्री शमीम ने जो कुछ कहा है उसके सिलसिले में मैं भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। मुस्लिम लीग का उन्होंने जिक्र किया है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जहां कहीं हमको धुंआ नजर आता है तो फौरन हमें पता चल जाता है कि वहां आग जरूर है। इसी तरह से जैसे ही मुस्लिम लीग का नाम हमको सुनने को मिलता है फौरन हमें 1945 और 1946 के हालात याद आ जाते हैं, तब जो नजारा देखने को मिला था, वह हमारे सामने आ जाता है। बेहतर यही है कि मुस्लिम लीग नाम को

ये न रखें, इस नाम को ही बदल दें तब सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। हिन्दुस्तान में कितनी ही पार्टियां हैं किसी भी पार्टी में वे शामिल हो सकते हैं। अगर शामिल नहीं होना चाहते हैं तो जैसे शमीम साहब ने कहा है वे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उनकी पार्टी जो आज हिन्दुस्तान में जगह-जगह जीत रही है उसमें शामिल हो सकते हैं। देर आयद, दुरुस्त आयद, अब भी अगर वे अपनी पार्टी का नाम बदल दें तो अच्छा होगा। नाम बदलने के साथ साथ काम भी उनको बदल देना चाहिये।

उर्दू की मुस्लिम लीग वाले बहुत वकालत करते हैं। लेकिन उसमें बहुत से मैम्बर ऐसे हैं जो उर्दू जानते तक नहीं हैं। इसके जो फाउंडर थे वह उर्दू नहीं जानते थे। हम उर्दू बोलने वाले हैं, बहुत अच्छी उर्दू हम बोलते हैं। जो नोट्स मेरे हाथ में हैं ये प्रिंट से भी अच्छे हैं, इसको आप देख सकते हैं। आंध्र में उर्दू की वकालत कौन कर रहे हैं, उसकी तरक्की के वास्ते कोशिश कौन कर रहे हैं, डा० राज बहादुर गौड़, श्री श्रीनिवास मूर्ति कर रहे हैं। श्रीमूर्ति मारवाड़ी हैं। उर्दू की तरक्की की वकालत की बात को मुसलमानों के साथ जोड़ना मैं समझता हूं कि उर्दू के साथ बड़ी बेइन्साफी करना है। उर्दू देश की ज़बान है। जो आदमी इस जबान का इस्तेमाल करता है उसकी यह ज़बान है। मुस्लिम लीग के मैम्बर मेहरबानी करके इसकी वकालत करना अगर छोड़ दें तो उर्दू के हित में यह बहुत अच्छी बात होगी। तब उर्दू फूलती-फलती जाएगी।

गुजरात में जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर वहाँ की विधान सभा को भंग करने की माँग भी की जा रही है। अपोज़ीशन का हमेशा यही रवैया रहा है। आँध्र में भी जब गड़बड़ शुरू हुई थी, आन्दोलन शुरू हुआ था तब भी वहाँ की विधान सभा को भंग करने की माँग की गई थी। लेकिन वह भंग नहीं की गई। वहाँ अब गवर्नमेंट बना दी गई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जहाँ-जहाँ जा रहे हैं पचास-पचास हजार आदमी आकर उनका स्वागत कर रहे हैं। गुजरात में भी यह टैम्पौरेरी फेज है। टैम्पोरेरी फेज में विधान सभाओं का भंग करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए।

जो आन्दोलन वहाँ हो रहा है वह क्यों हो रहा है? मैं समझता हूं कि मुल्क में अनाज की इतनी कमी नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। देश में अनाज काफी है। लेकिन उसका बटवारा ठीक तरीके नहीं हो रहा है। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने नए तरीके से अनाज के बटवारे का इंतजाम किया है। उससे बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा है। सेठ साहूकार तथा बड़े-बड़े लोग जो अनाज का ज़खीरा कर लिया करते थे और हर साल अपने एसैट्स को दुगना करते जा रहे थे सौ रु० फी क्विंटल अनाज खरीद कर और उसको छह महीने रख कर दो सौ रुपए में बेचा करते थे और इस तरह से अपनी आमदनी दुगनी करते जा रहे थे और गरीबों से ज्यादा पैसा वसूल किया करते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से अनाज की तकसीम का इंतजाम किया। उस इंतजाम को दरहम बरहम करने के वास्ते बहुत से अनासर कोशिश कर रहे हैं। ज़खीरा जो लोग कर लिया करते थे उनकी तरफ से जितनी पार्टियाँ अब तक बोली हैं उनको इससे धक्का पहुंचा है और उन्होंने यह तहैया कर लिया है कि मुल्क में बदअम्नी फैले और अनाज एक जगह से दूसरी जगह न पहुंच सके। आज पंजाब से, हरियाणा से, आँध्र से गुजरात को अनाज नहीं जा सकता है। इस तरह के हालात जो अपोज़ीशन पार्टीज़ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं वह देश की बदकिस्मती है। इसी की वजह से गड़बड़ पैदा हो रही है। इस साल हमारे पास काफी अनाज है। मैं अपनी काँस्टिट्युएंसी की बात आपको बताता हूं। मैंने कई दरखवास्तें दीं कि हमारे लोग लैवी देने को तैयार हैं, लेवी का चावल देने को तैयार हैं और मेरे कहने

[श्री एम राम गोपाल रेड्डी]

के ही बाद आठ दस दिन के बाद वहाँ अनाज ले लिया गया। 72 से 80 परसेंट अनाज मेरी कांस्टिट्यूएंसी में इकट्ठा किया गया। हमारे यहाँ 130 रुपए चावल का भाव है। जितना आप चाहें आपको वहाँ मोटा चावल मिल सकता है। लेकिन चार कदम पर महाराष्ट्र में उसी चावल की कीमत 260 से लेकर 400 रुपए के बीच मे है। मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें बीच में हायल है उसको आप तोड़ क्यों नहीं देते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो खुद-ब-खुद जो चावल वहाँ आँध्र में 130 रुपए में मिलता है वह महाराष्ट्र में जाकर 160 या 170 या 120 रुपए में बिकने लगेगा। वह 400 या 500 रुपए में नहीं बिकेगा। आप इस पर दुबारा सोचें। अगर थोड़े दिन के लिए हम फ्री ट्रेड एलाउ कर दें तो उसमें कोई नुक्सान नहीं होगा। काफी अनाज आँध्र में है। किसान वहाँ परेशान है। उसका अनाज बिक नही रहा है। महाराष्ट्र में जो खाने वाले हैं चूंकि उनको मिल नहीं रहा है इस वास्ते वे भी परेशान हैं। मै चाहता हूं कि इस पर भी आप विचार करें।

अब मैं डाक्टरों की स्ट्राइक के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। जिस नज़रिए से आपने एयरलाइज की स्ट्राइक को देखा या बैंक कर्मचारियो की स्ट्राइक को देखा उस नज़रिए से आपको डाक्टरों की स्ट्राइक को नही देखना चाहिए। वे बडी मेहनत करके और पढ़ लिख कर डाक्टर बने हैं। उनके साथ आपको हमदर्दी से पेश आना चाहिए, उनका आपको लिहाज़ करना चाहिए और उनको आपको ऊंची से ऊंची तनख्वाह देनी चाहिए। उनको कुचलने के बजाय, उनकी स्ट्राइक को तोडने के बजाय उनको बुला कर आप उनसे बातचीत करें तो अच्छा है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोझीकोड) : चेयरमैन साहब, मुझे यहाँ पर चन्द बातों की सफ़ाई करनी है। आज इस हाउस के सामने सब मामलात को साफ़-साफ़ तौर पर बयान करने की ज़रूरत है। इस हाउस में आप सब के सामने आपके एक रफ़ीक़ को, आप एक कालीग को, ग़द्दार कहा जाता है, यह कहाँ तक मुनासिब है, इसका फैसला आप ही करें। मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त, शमीम साहब, ने मुझे ग़द्दार करार देकर न जम्हूरियत की खिदमत की है और न इस हाउस के वकार को ही बढ़ाया है। (व्यवधान) उन्होंने ग़द्दार कहा है। (व्यवधान) वह खुद यहाँ मौजूद हैं। अगर वह कह दें कि उन्होंने ग़द्दार नही कहा है, तो मुझे खुशी होगी। और अगर उन्होंने कहा है, तो उसको वापिस लिया जाए, या उस को एक्सपंज किया जाए। अगर आप के ज़मीर जिन्दा हैं, तो यह बात मुनासिब नही होगी कि आपके एक साथी के बारे मे कोई शख्स कहता है कि वह ग़द्दार है और आप खामोश बैठे रहे। मै साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह इस हाउस के वकार का मसला है और ऐसा कहने मे इस हाउस का वकार नही बढ़ा है।

मै चाहता था कि जब मै इस डीबेट में हिस्सा लू, तो मै इस मुल्क के हालात, मुल्की मसायल और महगाई के मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डालू, और आज-कल जो लाक़ानूनियत फैली हुई है, उसको किस तरह रोका जाए, उसके बारे में अर्ज़ करूं। लेकिन यहाँ पर जो इल्ज़ामात लगाए गये है, उनके सिलसिले मे जवाब देना ज़रूरी हो गया है। इस लिए मै दूसरी तफ़सीलात मे नही जाना चाहता हूं।

उन्होने मुस्लिम लीग के बारे मे कहा है। मुस्लिम लीग क्या है, वह कौन सी तन्ज़ीम है, उसका दस्तुर—कांस्टीट्यूशन क्या है, उसकी पालिसी क्या है, यह मै जानता हूं या मेरे साथी जानते हैं या वे लोग जानते है, जो केरल से इलैक्ट हो कर आए है। केरल के मेरे साथियों को यह अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिम लीग की पालिसी क्या है।

सभापति महोदय : अब उत्तर प्रदेश के लोग भी कुछ जान गए होंगे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अगर आज यहाँ कल आए हुए काश्मीर के आजाद उम्मीदवार यह कहें कि मैं सब कुछ जानता हूं मुस्लिम लीग के बारे में, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह ग़लत होगा ।

श्री एस० ए० शमीम : मैं जानता हूं कि उसने पाकिस्तान बनाया है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : यह वह मुस्लिम लीग नही है, जिसने पाकिस्तान बनाया है । इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आल-इंडिया मुस्लिम लीग जुदा-जुदा है । इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मार्च, 1948 में राजाजी हाल मे कायम की गई थी, और उस का नया कांस्टीट्यूशम जनवरी, 1951 मे पास किया गया था ।

आप अच्छी तरह जानते है कि इस मुल्क में मुस्लिम लीग का क्या रोल और किरदार रहा है । हमने हमेशा यह कोशिश की है कि जहाँ इस्तहकाम न हो, वहाँ इस्तहकाम रखा जाए और जहाँ जम्हूरियत को ख़तरा हो, वहाँ उस का तहफ़्फुज किया जाए । हम न सिर्फ़ केरल में, बल्कि सारे मुल्क में, स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करते हैं और डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करते हैं, जम्हूरियत को बचाने की कोशिश करते हैं ।

पिछले इन्तख़ाब के बाद वैस्ट बंगाल में एक तरफ़ मार्किसस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी तरफ़ कांग्रेस पार्टी थी । ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने हम से यह दरख्वास्त की थी कि जम्हूरियत को बचाने के लिए हमें साथ देना चाहिए । तब वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मुश्तर्का, कोलीशन, गवर्नमेंट बनी थी ।

मुस्लिम लीग का कांस्टीट्यूशन आपके सामने मौजूद है । उस कांस्टीट्यूशन का पहला उसूल हिन्दुस्तान की आजादी और सालमियत का तहफ्फुज है—इंडिपेंडेंस एंड इनटेग्रिटी आफ़ दि कन्ट्री मस्ट बि सेफ़गार्डिड । उसका दूसरा उसूल है हिन्दू-मुस्लिम मफ़ाहमत-हारमोनियस रिलेशन्ज बिटवीन डिफ़रेंट कम्युनिटीज/उसका तीसारा उसूल है प्रोटेक्शन आफ राइट्स गारंटीड बाई दि कांस्टीट्यूशन । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस में कौन सी ऐसी बात है, जो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ़ हो, जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो । अगर यह कहा जाता है कि जो जमाउत कांस्टीट्यूशन के तहत कायम है, उसके मानने वाले ग़द्दार हैं, तो हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले शमीम साहब ख़ुद इस मुल्क के ग़द्दार है ।

जब 1965 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई, तो उस वक्त आंजहानी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक कान्फ़रेंस बुलाई थी । कौन-कौन उसमें मौजूद थे ? राजगोपालाचार्य, अन्नादुराई और इस्माईल साहब वहाँ मौजूद थे । इस्माईल साहब ने कहा कि हम इस मुल्क के लिए ख़ून का आख़िरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं । और हमने यह साबित किया ।

कौमी दायरे में न रहने की बात आप कहते ह और आप के शेख़ साहब कहते हैं । ये लोग कहाँ थे, जब हम मुल्क की सालमियत और ादीआज्ञ के लिए—उसकी इनटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए, 1965 की वार में और पाकिस्तान के साथ लास्ट वार में अपने मुल्क के साथ खड़े हुए ? मैने इस हाउस में इस बात का ऐलान किया था । हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मुल्क के साथ खड़े थे । हमने यह साबित किया है कि जब भी मुल्क पर आफ़त आई, या नाज़ुक वक्त आया हमने हमेशा मुल्क का साथ दिया ।

श्री एस० ए० शमीम : यह तकरीर मुरादाबाद में नहीं होती है, यह सिर्फ यहाँ पार्लियामेंट में होती है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : हम ने हर जगह यही बात कही है—मरादाबाद में भी कही है । उत्तर प्रदेश में मैं जहां भी गया हूं, मैं ने हिन्दू भाइयों और मुसलमान भाइयों से यही कहा है । मैं ने हिन्दु भाइयों से अपील की कि मुस्लिम लीग की ताईद कीजीए, हमारे दुख-दर्द को समझिए, ताकि यह साबित हो कि इस मुल्क में हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद कायम है । इसी तरह हमने केरल,

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेट]
वैस्ट बंगाल दूसरी जगह जो कुछ भी किया है, वह सब को मालूम है।

आपको मालूम है कि इस मुल्क का एक सैकुलर कास्टीट्यूशन है और यहां पर माइनारिटीज को तस्लीम करके उन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिये गए हैं, जिन को कास्टीट्यूशन मे गारंटी किया गया है । कास्टीट्यूशन में साफ तौर पर यह पूरा अख्त्यार दिया गया है कि माइनारिटीज अपनी जमाअत कायम कर सकती हैं और उस के बाद अपने कास्टीट्यूशनल राइट्स के लिए जद्दो-जहद कर सकती है, उनके लिए लड़ सकती है। तब यहा पर चीख-पुकार करने और किसी पर इल्जाम लगाने से कुछ नही होता है।

अगर हम अपने कॉंस्टीट्यूशनल राइट्स के बारे में कहते है, तो कहा जाता है कि हम फ़िरकापरस्त है । फ़िरकापरस्ती क्या चीज है? हम उसके मुखालिफ़ हैं । हम कभी फ़िरकापरस्त नही हो सकते, क्योंकि हम कांस्टीट्यूशन के तहत एक कौमी जमाअत हैं। हमने हमेशा हिन्दुस्तान के कास्टीट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, उसकी सालमियत और आज़ादी के लिए और हिन्दू-मुस्लिम मफ़ाहमत के लिए कोशिश की है।

जहा तक उर्दू जुबान का ताल्लुक है, हम कभी नही कहते है कि वह मुसलमानों की जबान है। तारीख हमारे सामने है। उर्दू हिन्दुस्तान में पैदा हुई, बढ़ी और पली। सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा है: "उर्दू लैंग्वेज इज़ दि कामन हेरिटेज आफ़ दि हिन्दूज़ एण्ड मुस्लिमज़"। बगाली मुसलमान बगाली बोलते हैं। केरल के मुसलमान मलयालम बोलते हैं । हम कभी नही कहते हैं कि उर्दू जुबान मुसलमानों की है। हा, अलबत्ता हम यह जरूर कहते हैं कि हमारा मजहबी और तहजीबी सरमाया उर्दू जुबान में मौजूद है, इस लिए उसका तहफ्फुज होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अपनी तहजीब और मजहब से आगाह हों।

इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हमारे मसायल हैं । शमीम साहब या और कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि हमारे मसायल हैं। माइनारिटीज़ हैव देयर प्राबलम्ज़ । और जब हम माइनारिटीज के लिए आवाज उठाते हैं, तो कहा जाता है कि तुम फिरकापरस्त हो । "हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम, वोह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नही होता।"

हिन्दुस्तान में क्या हालत है? मैं पूछना चाहता हू कि क्या हमारे साथ इन्साफ किया गया, क्या हमारे मुतालिबात पूरे किए गए, क्या हमें मुआशी बदहाली का शिकार नही बनाया गया, क्या हमें मुलाजिमतो से बेदखल नही रखा गया? हम चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तान की तरक्की में हिस्सा लें। वी मस्ट प्ले आवर रोल इन दि नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कहे, "हम वफ़ा करते रहे और वोह जफ़ा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज हम दोनो अदा करते रहे"।

आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दि सर्टिफिकेट आफ़ ए गुड गवर्नमेंट मस्ट कम फ्राम दि माइनारिटीज़---माइनारिटीज़ से यह सर्टिफिकेट आना चाहिए कि यह गवर्नमेंट अच्छी है, हर एक का ख़याल रखती है। और माइनारिटीज़ की वायस कौन बोल सकता है? माइनारिटीज की आर्गनाइजेशन ही बोल सकती है---वही माइनारिटीज़ की वायस हो सकती है।

SHRI S.A. SHAMIM Not necessarily.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट: कांस्टीट्यूशन के तहत माइनारिटीज़ की आर्गनाइजेशन हो सकती है। इस लिए हम पर यह जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यह फ़िरकापरस्त जमाअत है, वह ग़लत है ।

यहां पर मुसलमान रहते हैं। उनके मसायल हैं और उनको हल करना है। कांस्टीट्यूशन के तहत उनके कुछ राइट्स हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो राइट्स थे, उनकी हिफ़ाजत नहीं की गई। हम चाहते थे कि उसके माइनारिटी कैरेक्टर का ख़याल रखा जाए, क्योंकि वह माइनारिटी बैकवर्ड है। हम चाहते हैं कि कानून के जरिए शरह में मदाखलत न की जाए। हुकूमत एलान करती है कि शरह में मदाख़लत नहीं होगी, लेकिन बैकडोर तरीके से एडाप्शन के कानून में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तब्दीली करने की कोशिश की जाती है। जब हम इसके ख़िलाफ़ आवाज उठाते हैं, तो कहा जाता है कि यह ग़लत है। क्या कांस्टीट्यूशन दूसरों के लिए ही है।? क्या कांस्टीट्यूशन हमारे लिए नहीं है? क्या कांस्टीट्यूशन हमारे तहफ्फुज के लिए नहीं है।

हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई, हमारे बरादराने-वतन, हमें समझें। हम सब मिल-जुल कर यहां पर जिन्दगी बसर करें। हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। दस करोड़ इन्सान कहीं और नहीं जा सकते हैं। हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। हम मुहब्बत और इत्तिहाद के साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जेनेरासिटी, फ़राख़दिली, का सुलूक किया जाए—यह न किया जाए कि "मुंह पे डाले हुए पाबन्दीए-आइना का निकाब, सिर्फ़ अपनों के लिए दौर में जाम आता है"। हम समझें कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई और पारसी सब इस मुल्क के फूल हैं। इस गुलिस्तान के फूल हैं अगर सभी फूल लहलहाते रहें, तभी यह कहा जाएगा कि गुलिस्तान शादाब है। अगर एक तरक्की करे और दूसरा तबाह हो जाए, तो कोई नहीं कह सकता कि मुल्क तरक्की कर रहा है। "चमन चमन ही नहीं जिस के गोशे-गोशे में कहीं बहार न आए, कहीं बहार आए। यह मैकदे की, यह साकीगरी की है तौहीन, कोई हो जाए जाम बकफ़, कोई शर्मसार आए"।

सारी बातें जो कही गई हैं वह गलत हैं। मैं उन्हें रिफ्यूट करता हूं। मुझे गद्दार कहने वाले, मुस्लिम लीग को गद्दार कहने वाले गद्दार हैं (जो कुछ कहा गया मुस्लिम लीग के बारे में वह गलत है। कांस्टीट्यूशन हमें जो राइट देता है उन राइट्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं ...

श्री एस० ए० शमीम: यही तकरीर लखनऊ में भी कीजिए, यही तकरीर कानपुर में भी कीजिए। वहां मुसलमानों को उकसाया....

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : हमने नहीं उकसाया। आप उकसाते हैं हम उकसाते हैं।

.... (**व्यवधान**) ....

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Member may please resume his seat. Nothing that he speaks further will be recorded. Now, Shri Dhamankar.

[شری ابراهیم سلیمان سیٹ : (کاضی کوڈے) : چیر مین صاحب - مجھے یہاں پر چند باتوں کی صفائی کرنی ہے - آج اس هاؤس کے سامنے سب معاملات کو صاف صاف طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے - اس هاؤس میں آپ سب کے سامنے آپ کے ایک رفیق کو - آپ کے ایک کولیگ کو غدار کہا جاتا ہے - یہ کہاں تک مناسب ہے - اس کا فیصلہ آپ ہی کریں - میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست شمیم صاحب نے مجھے غدار قرار دے کر نہ جمہوریت کی خدمت کی ہے اور نہ اس هاؤس کے وقار کو ہی بڑھایا ہے - انہوں نے غدار کہا ہے - وہ خود یہاں موجود ہیں - اگر وہ کہہ دیں کہ انہوں نے غدار نہیں کہا ہے تو اس کو واپس لیا جائے - یا اس کو ایکسپنج کیا

[شری ابراهیم سلیمان سیٹ]

جائے اگر آپ کا ضمیر زنده هے تو یه بات مناسب نہیں هوگی - که آپ کے ایک ساتھی کے بارے میں کوئی شخص کہتا هے که وه غدار هے اور آپ خاموش بیٹھے هیں - میں صاف طور پر کہنا چاهتا هوں که یه اس هاؤس کے وقار کا مسله هے - اور ایسا کہنے سے هاؤس کا وقار نہیں بڑھا میں چاهتا تھا که جب میں اس ڈبیٹ میں حصه لوں تو میں اس ملک کے حالات ملکی مسائیل اور مہنگائی کے متعلق کچھ روشنی ڈالوں اور آج کل جو لا قانونیت پھیلی هوئی هے اس کو کس طرح روکا جائے - اس کے بارے میں عرض کروں - لیکن یہاں جو الزامات لگائے گئے هیں - ان کے سلسلے میں جواب دینا ضروری هو گیا هے - اس لئے میں دوسری تفصیلات میں نہیں جانا چاهتا هوں -

انہوں نے مسلم لیگ کے بارے میں کہا هے - مسلیم لیگ کیا هے وه کون سی تنظیم هے اس کا دستور کانسٹیٹیوشن کیا هے - اس کی پالیسی کیا هے - یه میں جاننا هوں یا که میرے ساتھی جانتے هیں - یا وه لوگ جانتے هیں جو کیرل سے سلیکٹ هوکر آئے هیں - کیرل کے میرے ساتھیوں کو یه اچھی طرح معلوم هے که مسلم لیگ کی پالیسی کیا هے -

سبھا پتی مہودیه : اب اتر پردیش کے لوگ بھی کچھ جان گئے هونگے -

شری ابراهیم سلیمان سیٹ : اگر آج یہاں کل آئے هوئے کشمیر کے آزاد امیدوار یه کہیں که میں سب کچھ جانتا هوں مسلم لیگ کے بارے میں تو آپ اندازه لگا سکتے هیں که وه غلط هوگا -

شری ایس - اے - شمیم : مبں جانتا هوں که اس نے پاکستان بنایا هے -

شری ابراهیم سلیمان سیٹ : یه وه مسلیم لیگ نہیں هے جس نے پاکستان بنایا هے - انڈین یونین مسلم لیگ اور آل انڈیا مسلم لیگ جدا جدا هیں - انڈین یونین مسلم لیگ مارچ ۱۹۴۸ مبں راجه جی هال میں قائیم کی گئی تھی - اور اس کا نیا کانسٹیٹیوشن جنوری ۱۹۵۱ مس پاس کیا گیا تھا -

آپ اچھی طرح جانتے هیں که اس ملک مبں مسلیم لیگ کا کیا رول اور کیا کردار رها هے - هم نے همیشه یه کوشش کی هے که جہاں استحکام نه هو وهاں استحکام رکھا جائے - اور جہاں جمہوریت کو خطره هو وهاں اس کا تحفظ کیا جائے - هم نه صرف کیرل میں بلکه سارے ملک مبں سٹیبلیٹی کے لئے کوشش کرتے هیں - جمہوریت کو بچانے کی کوشش کرتے هیں -

پچھلے انتخاب کے بعد ویسٹ بنگال میں ایک طرف مارکسٹ کمیونسٹ پارٹی تھی اور دوسری طرف کانگریس پارٹی تھی - خود پرائم منسٹر نے هم سے یه درخواست کی تھی که جمہوریت کو

کہتے ہیں - یہ لوگ کہاں تھے - جب ہم ملک کی سالیت اور آزادی کے لئے - اس کی انٹیگریٹی اور انڈیپینڈینس کے لئے ۱۹٦۵ کی وار اور پاکستان کے ساتھ لاسٹ وار میں - اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے - میں نے اس ہاؤس میں اس بات کا اعلان کیا تھا - ہم لوگ اپنے پرائیم منسٹر اور ملک کے ساتھ کھڑے تھے - ہم نے یہ ثابت کیا ہے - کہ جب بھی ملک پر آفت آئی یا نازک وقت آیا ہم نے ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا -

شری ایس - اے - شمیم : یہ تقریر مرادآباد میں نہیں ہوتی ہے - یہ صرف یہاں پارلیمینٹ میں ہوتی ہے -

شری ابراہیم سلیمان سینٹ : ہم نے ہر جگہ یہی بات کہی ہے - مرادآباد میں بھی کہی ہے - اتر پردیش میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے ہندو بھائیوں اور مسلمان بھائیوں سے یہی کہا ہے - میں نے ہندو بھائیوں سے اپیل کی کہ مسلم لیگ کی تائید کیجئیے - ہمارے دکھ درد کو سمجھنے - تا کہ یہ ثابت ہو کہ اس ملک میں ہندو مسلم اعتبار قائم ہے - اس طرح ہم نے کیرل - ویسٹ بنگال اور دوسری جگہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے -

آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کا ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے - اور یہاں پر مائنیورٹیز کو تسلیم کر کے ان کو کچھ فنڈامینٹل رائٹس دیئے گئے ہیں - جن کو کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی

بچانے کے لئے ہمیں ساتھ دینا چاہئیے - تب وہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ کی مشترکہ کولیشن گورنمینٹ بنی تھی -

مسلم لیگ کا کانسٹیٹیشن آپ کے سامنے موجود ہے - اس کانسٹیٹیوشن کا پہلا اصول ہندوستان کی آزادی اور سالمیت کا تحفظ ہے - انڈیپینڈینس اینڈ انٹیگریٹی آف دی کنٹری مسٹ بی سیفگارڈڈ - اس کا دوسرا اصول ہے - ہندو مسلم مفاہمت ہارمونیس ریلیشن بیٹوین ڈفرینٹ کمیونیٹیز اس کا تیسرا اصول ہے - پروٹیکشن آف رائٹس گرانٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کونسی ایسی بات ہے - جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو - جو ملک کے خلاف ہو - اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو جماعت کانسٹیٹیوشن کے تحت قائم ہے اس کے ماننے والے غدار ہیں - تو ہم پر الزام لگانے والے شمیم صاحب خود اس ملک کے غدار ہیں -

جب ۱۹٦۵ میں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوئی تو اس وقت آنجہانی شری لال بہادر شاستری نے ایک کانفرینس بلائی تھی - کون کون اس میں موجود تھے - راجگوپال آچاریہ - انادورائی اور اسمائیل صاحب وہاں موجود تھے - اسمائیل صاحب نے کہا کہ ہم اس ملک کے لئے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لئے تیار ہیں - اور ہم نے یہ ثابت کیا -

قومی دائرے میں نہ رہنے کی بات آپ کہتے ہیں - اور آپ کے شیخ صاحب

[شری ابراھیم سلیمان سیٹھ]

کیا گیا ھے۔ کانسٹیٹیوشن میں صاف طور پر یہ پورا اختیار دیا گیا ھے کہ مانیورٹیز اپنی جماعت قائم کر سکتی ھے۔ اور اس کے بعد اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لئے جدو جہد کر سکتی ھیں ان کے لئے لڑ سکتی ھیں - تب یہاں پر چیخ و پکار کرنے اور کسی پر الزام لگانے سے کچھ نہیں ھوتا ھے -

اگر ھم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائیٹس کے بارے میں کہتے ھیں۔ تو کہا جاتا ھے کہ ھم فرقہ پرست ھیں۔ فرقہ پرستی کیا چیز ھے۔ ھم اسکے مخالف ھیں۔ ھم کبھی فرقہ پرست نہیں ھو سکتے۔ کیوں کہ ھم کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک قومی جماعت ھیں۔ ھم نے ھمیشہ ھندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو اپ ھولڈ کرنے کے لئے اس کی سالمیت اور آزادی کے لئے اور ھندو مسلم مفہامت کے لئے کوشش کی ھے۔

جہاں تک اردو زبان کا تعلق ھے۔ ھم کبھی نہیں کہتے ھیں کہ وہ مسلمانوں کی زبان ھے۔ تاریخ ھمارے سامنے ھے۔ اردو ھندوستان میں پیدا ھوئی بڑھی اور پلی۔ سر تیج بہادر سپرو نے کہا ھے۔ ''اردو لینگویج از دی کامن ھیریٹیز آف دی ھندوز اینڈ مسلمز،، بنگالی مسلمان بنگالی بولتے ھیں کیرل میں مسلمان ملیا لم بولتے ھیں۔ ھم کبھی نہیں کہتے ھیں کہ اردو زبان مسلمانوں کی ھے - البتہ ھم یہ ضرور کہتے ھیں - کہ ھمارا مزھبی اور تہزیبی سرمایہ اردو زبان میں موجود ھے - اس لئے اس کا تحفظ ھونا چاھئے - تاکہ ھمارے بچے اپنی تہزیب اور مزھب سے آگاہ ھوں -

اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ھے کہ ھمارے مسائیل ھیں - شمیم صاحب یا اور کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ھے کہ ھمارے مسائیل ھیں - مانیورٹیز ھیئو دیئر پرابلمز - اور جب ھم مانیورٹیز کے لئے آواز اٹھاتے ھیں - تو کہا جاتا ھے کہ تم فرقہ پرست ھو -

ھم آہ بھی کرتے ھیں تو ھو جاتے ھیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ھیں تو چرچہ نہیں ھوتا

ھندوستان میں کیا حالت ھے - میں پوچھنا چاھتا ھوں کہ کیا ھمارے ساتھ انصاف کیا گیا - کیا ھمارے مطالبات پورے کئے گئے - کیا ھمیں معاشی بد حالی کا شکار نہیں بنایا گیا - کیا ھمیں ملازمتوں سے بے دخل نہیں کیا گیا - ھم چاھتے ھیں کہ ھم ھندوستان کی ترقی میں حصہ لیں - وی مشٹ پلے آور رول ان نیشنل ڈولپمینٹ لیکن ھم مجبور ھو جاتے ھیں کہ ھم کہیں کہ -

ھم وفا کرتے رھے اور وہ جفا کرتے رھے
اپنا اپنا فرض ھم دونوں ادا کرتے رھے -

آنجہانی پنڈت جواھر لال نہرو نے کہا تھا کہ دی سرٹیفکیٹ آف دی گوڈ گورنمینٹ مسٹ کم فروم دی مانیورٹیز -

مانیورٹیز سے یہ سرٹیفکیٹ آنا چاہئے - کہ یہ گورنمینٹ اچھی ہے - ہر ایک کا خیال رکھتی ہے - اور مانیوٹیز کی وائیس کون بول سکتا ہے - مانیورٹیز آرگینائیزیشن ہی بول سکتی ہے - وہی مانیورٹیز کی وائیس ہو سکتی ہے -

شری ایس - اے - شمیم : Not Necessarily.

شری ابراھیم سلیمان سیٹ : کانسٹیٹیوشن کے تحت مانیورٹیز کی آرگنائیزیشن ہو سکتی ہے - اس لئے ہم پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ پرست جماعت ہے - وہ غلط ہے - یہاں پر مسلمان رہتے ہیں - ان کے مسائیل ہیں اور ان کو حل کرنا ہے - کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے کچھ رائیٹس ہیں - علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو رائیٹس تھے ان کی حفاظت نہیں کی گئی - ہم چاہتے تھے کہ اس کے مانیورٹیز کریکٹر کا خیال رکھا جائے - کیونکہ وہ مانیورٹی بیکورڈ ہے - ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے ذریعے شروع میں مداخلت نہ کی جائے - لیکن بیک ڈور طریقے سے اڈاپشن کے قانون میں اور کریمینل پروسیزر کوڈ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے - جب ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں - تو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے - کیا کانسٹیٹیوشن دوسروں کے لئے ہی ہے - کیا کانسٹیٹیوشن ہمارے لئے نہیں ہے -

ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی - ہمارے برادران وطن ہمیں سمجھیں - ہم سب مل جل کر یہاں پر زندگی بسر کریں - ہم کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں - دس کروڑ انسان کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں - جئینگے اور یہیں مرینگے - ہم محبت اور اتحاد کے ساتھ رہینگے - ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراخدلی کا سلوک کیا جائے - یہ نہ کیا جائے کہ :-

منہہ پر ڈالے ہوئے پابند ٴ آئین کا نقاب
صرف اپنوں کے لئے دور میں جام آتا ہے -

ہم سمجھے کہ ہندو - مسلمان - سکھ - عیسائی ااور پارسی سب اس ملک کے پھول ہیں - اس گلستان کے پھول ہیں - اگر سبھی پھول ھل ھلاتے رہیں تبھی کہا جائیگا کہ گلستان شاداب ہے - اگر ایک ترقی کرے اور دوسرا تباہ ہو جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے -

چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں کہیں بہار نہ آئے - کہیں بہار آئے - یہ میکدے کی - یہ ساقی گری کی ہے توہین - کوئی ہو جائے جام بکف اور کوئی شرم سار آئے -

ساری باتیں جو کہی گئیں وہ غلط ہیں - میں انہیں رفیوٹ کرتا ہوں - مجھے غدار کہنے والے - مسلم لیگ کو غدار کہنے والے غدار ہیں - جو کچھ کہا گیا مسلم لیگ کے بارے

[شری ابزاهیم سلیمان سیٹ]
میں وہ غلط ہے - کانسٹیٹیوشن ہمیں جو رائیٹس دیتی ہے ان رائیٹس کے لئے ہم فائیٹ کر رہے ہیں -

شری ایس - اے - شمیم : یہی تقریر لکھنئو میں بھی کیجئے - یہی تقریر کانپور میں بھی کیجئے - وہاں مسلمانوں کو اکسایا -

سری ابراهیم سلیمان سیٹ : ہم نے نہیں اکسایا - آپ اکساتے ہیں - ہم اکسانے ہیں -]

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi) : I rise to support the Motion of Thanks moved by my hon. friend Shri Das-chowdhary.

The President has very abiy dealt with the problems before this country. He has dealt with two problems mainly, in a very extensive way; the first is the price rise and the shortage of foodstuffs and essential goods and the other is our foreign policy.

About price rise, much has been said in this House. There are shortages, and the Government at the Centre or at the State level is not in a position to give the minimum quantum of food-stuffs where there is statutory rationing. The prices are rising every month or rather every week and the State Governments have been asked to speed up their procurement. But they have not been in a position to procure even to the extent of 40 per cent of the target given to them. I think that there is something fundamentally wrong with the procurement policy. The agriculturist or the producer feels that even though the prices offered to him now are higher than those of last year, yet compared to the cost inputs, the prices offered are much lower. I think the Ministry of Agriculture should review the policy and see if this levy can be taken from the agriculturist in lieu of the inputs to be supplied to him at concessional rates. If that is done, it will make the agriculturist feel that he is giving his produce to Government for mass consumption of the people and for helping the country and he will apply more inputs into his land and grow more. I would suggest that the Agriculture Ministry may examine this suggestion and thus modify the policy so that procurement may yield some amount of success.

Secondly, if we are not in a position ot have enough procurement, and if our foreign exchange does not allow us to import foodgrains, I would like to ask Government why we should take the responsibility of feeding all categories of people at all levels. There is at present statutory rationing in industrial areas and industrial towns like Bombay, Nagpur, Sholapur and so many other cities. Why should there be uniform rationing for all types of people, affluent people and also people in the lower income groups? The industrial labour and the people in the lower income group should be given adequate quantum of foodgrains at lesser rates while the affluent people should be given ration to the extent of 50 per cent at normal prices and for the remaining 50 per cent they can afford to pay more. What is actually happening in Bombay and other cities? Rice is being sold at Rs. 4 or 6 per kg. and people are buying it there. Instead of encouraging this black market by enforcing controls on movement at the disrtict level or the taluka level. I think that if the policy is changed and there is free movement of foodgrains, the position would be better. For instance, in the case of sugar we are supplied with a certain quantum at reduced rates and we can buy the rest of our requirement at Rs. 4.50 or whatever other price prevails in the market.

In regard to rationing also, I think a different system should be evolved for the affluent class of people. Under this system, they will get 50 per cent of the quantum of ration at the normal, reduced government rates and they will buy the rest of the ration from the same

ration shop at a higher rate. The money thus realised should be utilised to pay more to the agriculturists who give their foodgrains to Government.

As regards the Adivasi and Harijan problem, there is a reference by the President in his Address. He said that some State sub-plans will be evolved. But that is not enough. Especially in regard to the education of Adivasis and Harijans, a new system has to be evolved. We are opening schools in small villages and tribal areas. Teachers have been appointed. But sometimes the teacher is there, sometimes he is not there, If he is there, we find there are three or four or five boys there. He is expected to teach at least 40 boys for that pay. The Adivasi boys are not in a position to attend the school because they have to take their cattle and sheep to the grazing field; they have also to do household work. So the Maharashtra Government tried an experiment under which the schools were taken to the grazing fields where the boys were grazing sheep. Along with that work, the teacher was teaching them. But that experiment also did not give any result. Then they started Ashram schools where the teacher lives with the Adivasi and tribal boys and girls the whole day and gives them education not only in theory but also agricultural and other type of education. We find in Maharashtra such schools functioning in a model way. Only last month, the Deputy Minister of Social Welfare visited such schools and he was very satisfied and impressed with the work done by these dedicated workers running the Ashram schools.

Then I want to refer to another thing. I am really very unhappy to make a mention of it here. I am a small, humble Congress worker who had the good fortune to work with Morarjibhai in the erstwhile Bombay State. Yesterday Morarjibhai made a certain statement here while speaking on firing by the police ten innocent people in Gujarat—that is what he said. Some boys were killed when they were flying kites on the verandas of their houses. Then he said that in Bombay when 105 people were killed, those who were killed were murderers and looters indulging in arson. This statement is far from truth.

श्री जांबुवंत धोटे (नागपुर) : ऐसा नहीं कहा।

SHRI DHAMANKAR : That is what I heard him say. I am open to correction. This statement of his is far from truth.

MR. CHAIRMAN : There is another business at 5.30. Does the hon. member wish to continue ?

SHRI DHAMANKAR: I will finish in a minute.

I really felt very hurt at this expression of Shri Morarji Desai. He should not have said it. I know examples of where women were killed when they were sitting in their kitchens on the second floor of chawls. Were they looters or murderers ? They were innocent people and they were killed. It happens when police resort to firing in mass disturbances.

श्री जांबुवंत धोटे : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt him. What is his point of order ?

श्री जांबुवंत धोटे : कब मोरारजी भाई की जो स्पीच हुई उस स्पीच में उन्होंने ऐसा नही कहा कि बम्बई में जो 105 लोग मारे गए वह लूटने वाले थे और लूटते वक्त उन को मारा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। रेकार्ड देखिए, यदि यह नहीं है तो इन्हे अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

सभापति महोदय : यह तो तथ्य का प्रश्न है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मोरारजी भाई ने यह कहा है कि दूकान लूटने वालों को हम ने मारा था।

श्री जांबुवंत धोटे : आप तो कांग्रेस के साथ हैं, यू०पी० में भी कांग्रेस के साथ थे · ·

श्री रामावतार शास्त्री : यह बात आप बोलना बन्द करिए · ·

श्री जांबुवंत धोटे : आप भी बोलना बन्द करिए।

मैंने कहा कि उन्होंने यह बात नहीं कही। प्रोसीडिंग देखिए · ·

सभापति महोदय : देखा जाएगा। (व्यवधान)।

Are you closing, or do you want to continue tomorrow ?

SHRI DHAMANKAR : At least two minutes more, if you are pleased to give me.

MR. CHAIRMAN : Then you continue tomorrow.

SHRI DHAMANKAR : Thank you.

17-31 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-SEVENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): Sir, I beg to present the Thirty-seventh Report of the Business Advisory Committee.

17-32 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PRODUCTION TARGET OF STEEL FOR 1974-75

SHRI D. D. DESAI (Kaira) : Mr. Chairman, Sir, we are on a very serious matter. The production of steel is almost stagnant since 1965-66, when the saleable steel was to the tune of 4.59 million tonnes. If we were to accept the figures given by the newly-formed authority, if we were to accept those figures given by Mr. Wadul Khan, then probably we would have been left with a target for 1974-75 of 4.45 million tonnes of saleable steel. This means a reduction in output of steel in spite of our larger investments in such a vital sector of the public undertakings. Planning Commission prodded up to 5.19 million tons.

The irony of India is that we have all the raw materials that we need to make the steel. It is well known that we have invested a large amount of capital not only in the steel plants but in the required capital eyuipment manufacturing plants. We have even developed a certain amount of technological basis to produce machines for the steel plants. With all that, with all the required raw materials within the reach of the steel plants, namely, iron ore, coking coal, ferro-manganese, dolomite, limestone, foldspar and even ths refractories, if we are not to progress in the production of steel, then I am afraid that the economy of the country is and will be seriously affected.

The difficulty runs like this. We now pay in Bombay about Rs. 5000 for a tonne of steel sheets in the open market. This is unheard of in any part of the world. We import about Rs. 200 crores worth of steel annually. One year back, the then Minister in charge of steel Ministry formed the Steel Authority of India Limited (SAIL) and it was expected to substitute the civil service culture by the industrial culture. Unfortunately after one year of SAIL operation we find that it has scaled down the target of steel whereas production should have been not less than 8 million tonnes. We are given a number of reasons like the power shortage, transport bottleneck, labour problems, scarcity of cocking coal and so on, but the basic fact is lack of utilisation of installed capacity. We cannot criticise the Minister, who took over recently, for the past failures. But we would naturally like him to see that the unutilised capacity of steel plants in which we have invested about 2100 crores of rupees is utilised. This capacity should be utilised to the full or at least 85 or 90 per cent should be utilised, because there are no constraints about steel consumption or production.